वर्ष : 16 ❖ अंक : 173 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
बुधवार, 02 फरवरी 2022

क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है : वित्त मंत्री 3

केंद्रीय बजट में कोई राजनीति नहीं : पीएम मोदी 8

कला राई ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

एसकेएम सरकार ने किए हैं उल्लेखनीय विकास : कला राई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । एसकेएम की महिला मोर्चा अध्यक्ष कला राई ने राज्य में एसकेएम सरकार के तीन साल की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तीन साल में विकास के अनेक कार्य किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा है।

यहां विशेष बातचीत में श्रीमती राई ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक काम किए हैं। राज्य सरकार की पहल पर एमबीबीएस की 50 सीटें राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित की गई है। ये सीटें राज्य के मेधावी गरीब छात्रों को बिना किसी शुल्क के मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से राज्य में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी सुधार संभव हो सकेगा और डाक्टरों की कमी से राज्य को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके साथ ही पांच सीटें आरसी होल्डर के लिए भी आरक्षित की हैं।

श्रीमती राई ने कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि धन के अभाव में किसी गरीब को उपचार से वंचित रहना पड़े। इसलिए सरकार ने बीपीएल परिवार को 20 हजार रुपए की मेडिकल सहायता की शुरुआत की है। वहीं सीओआई धारक को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से दो लाख रुपये तक प्रदान करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन भी में भी वृद्धि की है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिला ठेकेदारों को पांच करोड़ से कम के ठेके पर टीडीएस में छूट दी है वहीं 5 से 10 करोड़ के ठेके पर केवल एक प्रतिशत टीडीएस काटने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक ठेका प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपये तक के काम के लिए आनलाइन टेंडर नहीं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तीन साल में 3150 गरीब आवास योजना के घरों को स्वीकृति दी है। गरीब परिवारों के लिए एसयूजीए योजना शुरू की है। कालेज छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी के लिए मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा विकास फंड बनाया है। 105 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।

एसकेएम नेता ने कहा कि चालकों के हित के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की है। इसी क्रम में दुर्घटना में किसी चालक के मारे जाने पर उसके परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता देने की शुरुआत की गई है। सरकार ने 553 शिक्षकों को नियमित किया है। सरकार ने नामथांग, रिंचेनपोंग, जोरथांग कामलिंग में विश्वविद्यालयों के निर्माण का निर्णय लिया है। सरकार भाषा पर पीएचडी करने वालों को सहायता प्रदान कर रही है। अपने तीन साल के कार्यकाल में सरकार ने दो नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने हाल ही में दो डीआईजी रेंज बनाने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो राज्यभर में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की उन्नति का निर्णय लिया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में मुंबई में सिक्किम हाउस का निर्माण किया गया। 1975 से पहले से राज्य में रहने वालों के आरसी के मुद्दे को भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। सरकार के आने के बाद से स्थानीय स्तर पर दूध के उत्पादन और आर्गेनिक उत्पादों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि एसडीएफ साल अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में जो नहीं कर सकी वह हमने तीन साल में कर दिखाया है। पिछली सरकार केवल भाषणों में सीमित थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में काम जमीन पर नजर आ रहा है।

एसडीएफ ने 25 सालों तक किया शोषण और दमन : सी.पी. भट्टराई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता तथा पार्टी के साहित्य सचिव सीपी भट्टराई ने एसडीएफ पार्टी पर 25 सालों तक शोषण, दमन और अत्याचार करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग एसकेएम सरकार के द्वारा जनहित में किए जा रहे कामों पर बाधा डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उल्लेख किया है कि पवन चामलिंग छोटी मोटी बातों को उठाकर 25 वर्ष में हुई हिंसा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में अवहेलित वर्ग को फिर पवन चामलिंग के द्वारा उत्पन्न भ्रम को देखना आवश्यक है।

उन्होंने पवन चामलिंग को राजनीतिक नाटककार कहते हुए उन्हें उनके कार्यकाल के इतिहास को देखने की सलाह दी। उन्होंने एसडीएफ समर्थक और नेता पवन चामलिंग फिर से राज्य के गरीब, श्रमजीवी पर शोषण दमन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एसकेएम पार्टी इससे जनता को बचाने के लिए काम करेगी, यह पार्टी का रुख है।

उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि पवन चामलिंग ने गलत तरीके से धन संकलित किया है। हम सोचते थे कि 25 सालों तक उन्होंने सोने की खेती की लेकिन आज देखा जा रहा है कि उन्होंने जनता के सामने झूठ की खेती की। उनका कहना है कि पवन चामलिंग के द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री को लगाए गए आरोप अकेलापन का हताशा ही है। प्रवक्ता शर्मा ने उल्लेख किया है कि एसकेएम के द्वारा लाया गया बसंत न देखकर शिशिर देखना चामलिंग के बूढ़े मस्तिष्क के कारण है।

मंत्री उप्रेती ने रिंपोछे के कुडुंग के किए दर्शन

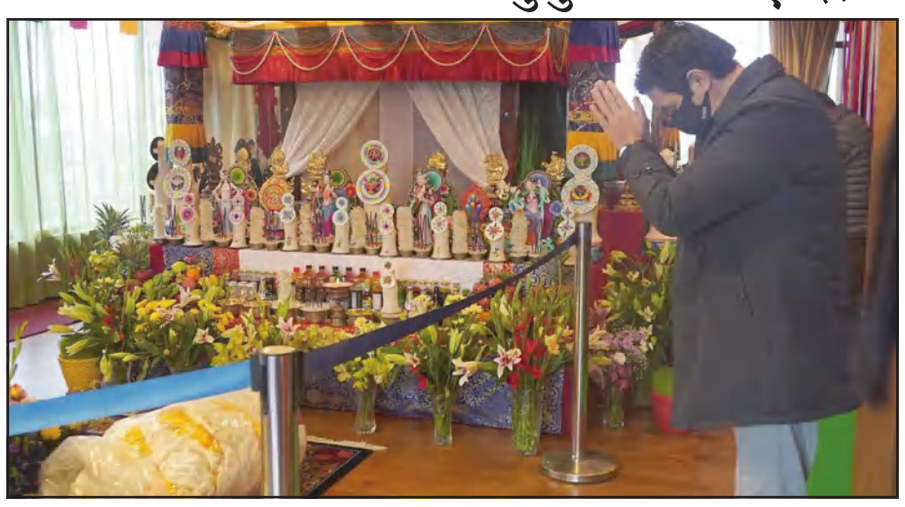

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । सिक्किम सरकार के मंत्री अरुण उप्रेती ने आज गंगटोक के नजदीक (हनुमान टोक) परिसर स्थित फुंत्सोक नाग्याप पेलरी मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर का दौरा किया।

उन्होंने गत 25 जनवरी 2022 को महापरिनिर्वाण प्राप्त करने वाले चौथे क्याब्जे दोद्रुपचेन रिंपोछे के कुडुंग के दर्शन किए।

मंत्री उप्रेती ने धर्म विभाग के मंत्री सोनाम लामा के साथ परम पावन चौथे क्याब्जे दोद्रुपचेन रिंपोछे की प्रार्थनाओं से संबंधित व्यवस्थायों का जायजा लिया और समिति के साथ बैठक की।

राज्यपाल ने लोसार पर्व की दी शुभकामनाएं

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने लोसार/सोनम लोसार पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सिक्किमवासियों को अपने सन्देश में कहा कि-यह त्योहार हमारे जीवन में एक उम्मीद एवं आशा की किरण के साथ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेगा।

इस पर्व के माध्यम से सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना जैसे गुणों का विकास हो। हम सभी आपसी एकता एवं सामंजस्य के साथ प्रदेश हित और राष्ट्रहित की चिंता करें, ऐसी भावना को जागृत करना वर्तमान समय की मांग है।

राजभवन में आज राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद क्योंगस्ला ग्राम पंचायत के अध्यक्ष इंद्र कुमार रसाइली को ग्राम पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय के विकास हेतु पांच लाख रुपये की राशि चेक प्रदान करते हुए।

केवल वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है सिक्किम की राजनीतिक पार्टियां : मदन तमांग

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों पर सिक्किम के हित में नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए राजनीति करने का आरोप सिक्किम सुरक्षा समिति ने लगाया है। समिति के अध्यक्ष मदन तमांग ने एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित करते हुए कहा है कि राज्य की सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियां केवल कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं।

अध्यक्ष तमांग ने आज कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण आज असली सिक्किमी नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है। राज्य में जाली सिक्किम सब्जेक्ट, सीओआई और आरसी बनाकर सिक्किमी नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस विषय में राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और सरकार के मुख्य सचिव को भी ज्ञापन सौंपा गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में पशुपालन विभाग के निदेशक भक्तिमान छेत्री को निदेशक से पदोन्नत कर प्रधान निदेशक बनाया है।

उन्होंने कहा है कि भक्तिमान छेत्री पश्चिम बंगाल के पेदोंग निवासी हैं। उनका सीओआई साल 2016 में ही रद्द किया जा चुका है। फिर भी राज्य सरकार ने उन्हें पदोन्नति दी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस निर्णय को 15 दिन के अंदर वापस नहीं लिया गया तो समिति दूसरा कदम उठा सकती है। उन्होंने पूर्व जिले के डेवलपमेंट एरिया में घर निर्माण कर रहे रुद्र प्रसाद बाहुन का भी सीओआई जाली होने का दावा किया। अध्यक्ष तमांग के मुताबिक रुद्र प्रसाद बाहुन के सीओआई में जो सीरियल नंबर और वोल्युम नंबर है वह पुराने डक्यूमेंट से मेल नहीं खाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक पार्टियों को सिक्किम के भविष्य की चिंता नहीं है। ऐसे चुप रहकर बैठना सिक्किम के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्रों में सिक्किम की सुरक्षा के लिए किए गए वादे केवल झूठे हैं।

जैविक खेती की प्रगति की सीएम ने की समीक्षा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) की अध्यक्षता में आज सम्मान भवन में जैविक मिशन और उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि मंत्री श्री लोकनाथ शर्मा भी उपस्थित थे।

बैठक में राज्य में जैविक खेती के अभ्यास में अधिक सटीकता लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ज्ञात हो कि जैविक खेती को पारंपरिक सिक्किमी तरीके से खेती करने वाली कृषि प्रणाली के रूप में माना जाता है। कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों ने सदन को जैविक मिशन और इसे बढ़ाने और इससे युवाओं को जोड़ने और जमीनी स्तर पर इसे बढ़ावा देने की उनकी पहल के बारे में जानकारी दी।

सरकार ने सिमफेड की देखरेख में एक समर्पित जैविक बाजार बनाने का फैसला किया है जहां केवल जैविक उत्पाद ही बेचे जाएंगे, जो राज्य में किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए फायदेमंद होगा। बैठक में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) को सिमफेड के सहयोग से सिक्किम के जैविक उत्पादों के प्रचार और विपणन की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया। कंपनी सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक वैल्यू चेन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बैठक में मुख्य सचिव एससी गुप्ता, एसीएस वित्त, वीबी पाठक, एचसीएम के सचिव डॉ. एसडी ढकाल, सचिव कृषि, रिंगिंग सी. भूटिया, सचिव बागवानी बीबी सुब्बा, सचिव डीओपी केसी लेप्चा, एमडी सिमफेड भास्कर बस्नेत, कृषि, बागवानी और सहकारिता विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

विकास और विरासत को साथ लेकर चलने वाला बजट : रेड्डी

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने आम बजट को विकास और विरासत को साथ-साथ लेकर चलने वाला बजट बताते हुए कहा है कि इस बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह प्रगतिशील बजट है , इसमें इंफ्रास्ट्रक्च र पर विशेष ध्यान दिया गया है। लोगों के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि कई जगह टैक्स को कम किया गया है। उन्होंने बजट राशि के संबंध में राज्य सरकारों के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बजट की तारीफ करते (शेष पृष्ठ ०३ पर)

पवन चामलिंग पर हिंसा फैलाने के आरोप गलत : एम.के. सुब्बा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 01 फरवरी । एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग के सिक्किम आने के बाद राज्य में हिंसा फैलने के एसकेएम पार्टी के आरोपों का एसडीएफ प्रवक्ता एमके सुब्बा ने खंडन किया है।

उन्होंने कहा कि जब एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिंग बागडोगरा आए थे उस समय जनता की ओर से किए गए उनके स्वागत को देखकर एसकेएम को समस्या हो रही है।

इसी कारण एसकेएम पार्टी पवन चामलिंग पर विभिन्न आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि पवन चामलिंग करीब 50 साल से सिक्किम की सेवा कर रहे हैं। एसकेएम पार्टी उनके मन में जो आया उसी को बहाना बनाकर आरोप लगा रही है।

दूसरी ओर सिक्किम विधानसभा में लिम्बू-तमांग सीट आरक्षण, जनजाति से छूटी 12 जातियों को जनजाति की मान्यता और 17वें ग्यालवा कर्मापा उगेन थिनले दोरजी को सिक्किम लाने के संबंध में एसकेएम पार्टी ने जो समिति गठित की है यह जनता के आंख में धूल झोंकने के समान है।

प्रवक्ता सुब्बा ने आरोप लगाया कि इन तीनों मुद्दों पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसी कारण जनता को भ्रमित करने के लिए समिति का गठन किया है। उनका आरोप है कि तीनों मुद्दों का समाधान करने के लिए एसकेएम के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है।

उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि लिम्बू-तमांग सीट आरक्षण को लेकर अगर एसकेएम सरकार ईमानदार है तो इसका फार्मूला केंद्र को देकर जनता के समक्ष उसे सार्वजनिक करे।

उन्होंने कहा कि एसडीएफ के पास 40 सीट का फार्मूला है और अब तक एसडीएफ ने कितना काम किया यह जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में तमांग समुदाय से मुख्यमंत्री और लिम्बू समुदाय से लोकसभा सांसद है, फिर भी आसन आरक्षण के लिए ठोस कार्य न करना दुख का विषय है।

पर्यटन मंत्रालय के लिए बजट में 2,400 करोड़ का प्रावधान

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के लिए बजट में 2,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो गत साल की तुलना में 18.42 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में आवंटित राशि का अधिकतर हिस्सा स्वदेश दर्शन योजना के लिए है।

पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभारी हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के जरिये जब देश आजादी के 75 साल का उत्सव मना रहा है, तब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और यह बजट आजादी के 100 साल पूरे होने तक का ब्लूप्रिंट पेश करता है। विकास और विरासत साथ साथ चलते हैं और यह इस बात से परिलक्षित होता है कि इस साल पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए बजट में काफी अधिक राशि आवंटित की गयी है।

बजट में प्रस्तावित आवंटित 2,400 करोड़ रुपये में से 1,644 करोड़ रुपये आधारभूत ढांचा विकास तथा (शेष पृष्ठ ०३ पर)

बजट को विपक्ष ने बताया मिडिल क्लास के साथ विश्वासघात

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। विपक्ष ने मंगलवार को संसद में पेश 2022-23 के आम बजट के लिए सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात और युवाओं की जीविका पर आपराधिक प्रहार किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के बजट में किसी भी तरह के कर राहत की घोषणा नहीं की है, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मध्यम और वेतनभोगी वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्यम वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपने प्रत्यक्ष कर से संबंधित कदमों से इन वर्गों को बहुत निराश किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात है।

सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि क्या सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाकर क्रिप्टो करेंसी को बिना विधेयक लाए ही वैध करार दिया है?

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, बजट किसके लिए है? सबसे अमीर 10 प्रतिशत भारतीय देश की कुल संपत्ति के 75 प्रतिशत के स्वामी हैं। नीचे के 60 प्रतिशत लोग सिर्फ पांच प्रतिशत संपत्ति के मालिक हैं। महामारी के दौरान सबसे अधिक मुनाफा कमाने वालों पर अधिक कर क्यों नहीं लगाया गया?

उन्होंने दावा किया, शहरी रोजगार गारंटी के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। मनरेगा के लिए आवंटन पिछले साल के बराबर 73 हजार करोड़ रुपये रहा। युवाओं की जीविका पर आपराधिक हमला हुआ है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है । बड़ी-बड़ी बाते हैं और हकीकत में कुछ नहीं है। पेगासस स्पिन बजट है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि बजट से साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग की परवाह नहीं करते।

'युवाओं की जीविका पर प्रहार'

उन्होंने ट्वीट किया, हीरे सरकार के सबसे अच्छे मित्र हैं। किसानों, मध्य वर्ग, दिहाड़ी मजदूरों, बेरोजगारों की प्रधानमंत्री कोई परवाह नहीं करते।

हालांकि, वित्त मंत्री ने करदाताओं को कुछ राहत देते हुए घोषणा की कि अब दो साल के भीतर अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, 'बजट ने पीएम मोदी के बड़े व्यापारिक मित्रों के हितों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की समस्याओं को नहीं सुलझाया है। यह बजट केवल असमानता को बढ़ाएगा और हमारी आबादी के सबसे बड़े वर्ग को कमजोर कर देगा।'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'एक तरफ, बजट जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। दूसरी ओर, यह पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी नदी-जोड़ने वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है। बयानबाजी अच्छी लगती है। लेकिन कार्रवाई अधिक मायने रखती है। उस मोर्चे पर, मोदी सरकार विनाशकारी रास्ते पर है।'

निवेश की कमी से रुके प्रोजेक्ट्स पर काम होगा पूरा : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। रेल बजट के ऐलान के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निवेश की कमी के चलते कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। अब उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि रेलवे में सरकार के बजट की ओर से एक लाख 37 हजार करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया गया है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इससे निवेश की कमी की वजह से लंबे समय से जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, ''रेलवे के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सबसे महत्वपूर्ण ख़वाइंट्स थे, उन्हें बजट में शामिल किया है। रेलवे में सरकार के बजट की ओर से एक लाख 37 हजार करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया गया है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इससे निवेश की कमी दूर हो जायेगी और लंबे समय से जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही रेल मंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा कि स्टेशन के लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार है और 12 हजार करोड़ रुपये तीन महीने पहले ही मंजूर कर दिए गए थे, जिसे आगे लेकर जाता है। वंदेभारत ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह तकनीक का पहला वर्जन अभी चल रहा है और दूसरे वर्जन की डिजाइन पूरा हो गया है। उसका निर्माण चल रहा है और अप्रैल महीने से टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। बजट में अलग जेनरेशन के लिए तैयार करने का टारगेट दिया गया है। अगर वंदे भारत प्रीमियम कैटेगरी की होती तो ऑक्यूपेंसी कम होती। फिलहाल दोनों वंदे भारत ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी 95 फीसदी है।

रेल मंत्री ने कहा, कवच भारत में ही डेवलप टेक्नोलॉजी है। यह एक वर्ल्डक्लास टेक्नोलॉजी है। बजट के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे जगह दी है। देश में इस तकनीक को डेवलप करके विश्वभर में इसे एक्सपोर्ट करने का टारगेट लेना चाहिए। जिन देशों में बहुत अच्छा रेलवे नेटवर्क है, वहां इसे एक्सपोर्ट करना होगा।''

वहीं उन्होंने एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना पर कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू भी की जाएगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गतिशक्ति कार्गो का भी प्लान है।

उन्होंने कहा कि बजट से रेलवे के एकीकरण से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स समाधान आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार के अधिक अवसर आएंगे। उन्होंने कहा कि अगस्त सितंबर से फैक्ट्री से हर महीने 7-8 ट्रेनें निकलती नजर आएंगी। आने वाले तीन सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने की योजना है।

वहीं बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री ने कहा कि फिलहाल 5 किलोमीटर प्रति महीने पिलर बना रहे हैं, लेकिन इसे 10 किलोमीटर तक हर महीने लेकर जाना है। अभी काम कल रहा है। इसके साथ ही ट्रेन में बेडिंग की सेवा फिर से शुरू करने पर उन्होंने कहा कि यह सेवा कुछ वक्त में चालू हो जाएगी। ओमिक्रॉन की वजह से इसे टाला गया था।

इसके साथ ही रेलवे भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि आरआरबी की नॉन टेक्निकल लोकप्रिय कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्रालय काम कर रहा है। रेलवे एक स्थिर और दीर्घकालिक संस्थान है। यहां लोग नौकरी करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, हमने आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की साल 2019 में घोषणा की थी। इसके लिए टीसीएस को भी नियुक्त किया गया था। कोरोना महामारी के बाद भी हमने ट्रांसपेरेंसी से परीक्षा करवाई है। छात्रों को कुछ समस्याएं थीं, जिनका हम लोग समाधान करेंगे। अभी तक एक लाख से ज्यादा छात्रों के रिप्रेजेंटेशन आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी ट्रेन में पेपर बिछाकर स्लीपर में सफर किया है। मुझे एहसास है इन छात्रों की परेशानी का।

जेब में रखते हैं जालीदार टोपी, माथे का टीका भी नहीं पसंद : केशव मौर्य

लखनऊ, 01 फरवरी (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ के सरधना में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो लाल टोपी लगाकर और जालीदार टोपी जेब में रखकर घूमते हैं, उन्हें जवाब देना होगा। अखिलेश यादव को न कोरोना का टीका पसंद है, न माथे का टीका पसंद है। भाजपा की सरकार गरीबों महिलाओं युवाओं के लिए काम करती है। अगर सपा गठबंधन यूपी के 24 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है तो भाजपा गठबंधन 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है।

उन्होंने कहा कि सपा सरकार में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते सिर्फ धर्म विशेष की बेटियों को सरकारी योजना का लाभ मिलता था। वहीं भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए कन्या सुमंगला योजना से बिना भेदभाव सभी बेटियों को जन्म से स्नातक तक छह चरणों में आर्थिक मदद की गई। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने शासनकाल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ किसानों को ठगने का काम किया है। वहीं भाजपा सरकार में किसान को सम्मान मिला और उचित मूल्य का भुगतान किया गया। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया। किसान सम्मान निधि के तहत 2.55 करोड़ किसानों को 42,565 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। पांच सालों में 1.52 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। किसानों के उपज की दोगुनी खरीद की गई और एमएसपी को भी डेढ़ गुना किया गया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के शासनकाल में माफिया और अपराधी खुलेआम घूमते थे और पुलिस भी अपराधियों से डरती थी। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनीं तो हमने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता में रखा। अपराधी और माफियाओं को जेल भेजा। प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली। लोग इस बात को भूले नहीं हैं। उन्होंने जनता से एकबार फिर भाजपा को जिताने की अपील की। साथ ही कहा कि 10 मार्च को भारी बहुमत से फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है।

मंदिर में काम करने वाले पुजारियों को देंगे मानदेय : अखिलेश यादव

लखनऊ, 01 फरवरी (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मंगलवार को कई ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट किया और उन्हें अपने समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी बातें धैर्य से सुनने और मांग पत्र में दी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया।

विधायक विनय तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे ब्राह्मण संगठनों ने मांग पत्र में कहा है कि भगवान परशुराम की जयंती पर पूर्व में दिए गए सार्वजनिक अवकाश को पुन: बहाल किया जाए। ब्राह्मण आयोग का गठन हो। ब्राह्मण एवं ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात को रोका जाए। संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष की शिक्षक को प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गरीब सवर्णों को भी सभी जरूरी सुविधाएं दी जाए। मंदिर में कार्यरत पुजारियों को जीवन यापन भत्ता दिया जाए। परशुराम जन्मस्थली का सौन्दयीकरण एवं उसको तीर्थस्थल घोषित किया जाए। लखनऊ के किसी एक प्रमुख चौराहे को परशुराम चौक के रूप में नामित कर विकसित किया जाए। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न बंद किया जाए तथा ब्राह्मण बेटी खुशी दुबे को रिहा कर उस पर लगे झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए।

अखिलेश यादव ने ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि समाजवादी सरकार बनने पर संस्कृत शिक्षकों का सम्मान होगा। मंदिरों का संरक्षण होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों सहित मंदिरों के अन्य पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा। रामायण के कलाकारों को भी मानदेय देंगे। श्रवण यात्रा फिर शुरू होगी। ब्राह्मणों सहित सभी पर लगे फर्जी मुकदमें वापस लिए जाएंगे। समाजवादी सरकार बनने पर पुरोहितों को भी मानदेय देंगे।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी सरकार में तीर्थ स्थलों के विकास के साथ संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। पूर्व की समाजवादी सरकार में संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को 30 करोड़ की मदद दी गई थी। परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। भेंट करने वाले ब्राह्मण प्रतिनिधियों में विधायक विनय शंकर तिवारी, विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (ब्रह्म समर्पित) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद्र शर्मा, महामंत्री ब्राह्मण संघ हरीश शर्मा, ओम ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी, ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष के.पी. शर्मा सहित सर्वश्री ब्रह्मदेव शर्मा, अशोक पाण्डेय, डॉ0 साधना मिश्रा, सुधांशु पाठक, प्रवीण शर्मा, गौतम आदि शामिल थे।

अभिषेक बनर्जी के सचिव को हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी राहत

कोलकाता, 01 फरवरी (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के सचिव सुमित रॉय को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कथित कोयला घोटाले की जांच में मदद करने के लिए एजेंसी के समक्ष पेशी के दौरान सुमित रॉय को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

रॉय के वकीलों ने सीबीआई की उस नोटिस को उच्च चुनौती दी जिसमें उन्हें (रॉय) मंगलवार को यहां पेश होने के लिए कहा गया था। वकीलों ने दावा किया कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया है और कोयला घोटाले से संबंधित प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि रॉय मंगलवार सुबह सीबीआई के कार्यालय गए थे और उनसे दोपहर के भोजन के बाद लौटने का अनुरोध किया गया था। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में मंगलवार को सुमित रॉय से करीब साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की है। सुबह से चल रही पूछताछ शाम को खत्म हुई।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जांच में शामिल होने के लिए नोटिस मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाना अब एक प्रचलन सा बन गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाए बिना कार्यवाही के इस चरण में रिट अदालत के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है।

जस्टिस आर के कपूर ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच अधिकारियों के साथ अपना सहयोग फिर से शुरू करने पर सीबीआई द्वारा 25 जनवरी को जारी नोटिस के अनुसार उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख घरों का होगा निर्माण, 3.8 करोड़ घरों को मिलेगा नल से जल

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा, '2022-23 में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।' वित्त मंत्री ने आगे कहा कि शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए सभी भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरी के लिए आवश्यक समय में कमी के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ काम करेगी।

वित्त मंत्री ने आगे कहा, 'हम बिचौलियों की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वित्तीय क्षेत्र, नियामकों के साथ भी काम करेंगे।'

निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है।

फ्यूचर ग्रुप के लिए बड़ी राहत, सख्त कदमों के लिए हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को मंगलवार को खारिज कर दिया।

खारिज किए गए आदेशों में वह आदेश भी शामिल है, जिसमें विलय के सौदे पर आगे बढ़ने से एफआरएल को रोकने वाले मध्यस्थ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे पर मध्यस्थ के फैसले संबंधी फ्यूचर ग्रुप कंपनियों की याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 के आदेशों और 29 अक्टूबर, 2021 के आदेश को रद्द करते हैं। हम (उच्च न्यायालय के) विद्वान न्यायाधीश को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले पर विचार करें और टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करें। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले के शीघ्र निपटान के लिए एक पीठ का गठन करें।

अमेरिका की ई-कॉर्म्स कंपनी अमेजन रिलायंस रिटेल और एफआरएल के 24,731 करोड़ रुपए के विलय सौदे के साथ आगे बढ़ने के फ्यूचर समूह के फैसले का विरोध कर रही है।

सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) ने अपने आपात निर्णय (ईए) में फ्यूचर समूह को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे को लेकर आगे बढ़ने से रोक कर अमेरिकी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। ईए को अक्टूबर 2021 में मध्यस्थ के अंतिम फैसले में बरकरार रखा गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता केंद्र के अंतिम फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उसने एक अन्य आदेश में उसने फ्यूचर ग्रुप और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था और उनकी संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था।

डिजिटल मैराथन से लड़कियों तक पहुंच रही है कांग्रेस

लखनऊ, 01 फरवरी (एजेन्सी)। यूपी में 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस महिला सशक्तीकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। घोषणापत्र और चुनावी वादों से इतर कांग्रेस 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' मैराथन के जरिये लड़कियों तक पहुंची और यह सिलसिला अब भी जारी है। फिजिकल रैलियों पर रोक लगने के बाद कांग्रेस अब डिजिटल मैराथन के जरिये लाखों छात्राओं तक पहुंच रही है।

महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट, महिलाओं के लिए अलग से घोषणापत्र, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी के अलावा भी कांग्रेस के पास महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। लड़कियों के मैराथन में उमड़ रही भारी भीड़ को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित थी, लेकिन कोविड के चलते फिजिकल मैराथन रोकनी पड़ी। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तय किया कि कांग्रेस अब डिजिटल रैलियों की तरह डिजिटल मैराथन भी कराएगी।

इसके लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेज की मदद ली गई और अब तक इसके लिए 5 लाख लड़कियां रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।

इस डिजिटल मैराथन में भी विजेता लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन दिया जाना है। कांग्रेस की कोशिश है कि वह चुनाव से पहले मैराथन के जरिये तमाम लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दिला सके ताकि उसके वादे महज चुनावी न लगें।

महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में भी महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र लाने जा रही है। यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर पंजाब में नारा दिया गया है 'धी पंजाब दी, अपना हक जाणदी'।

बीजेपी की नई लिस्ट आई, स्वाति सिंह का टिकट कटा

लखनऊ, 01 फरवरी (एजेन्सी)। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई सूची आ गई है। इसमें 17 उम्मीदवारों के नाम हैं। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राजेश्वर सिंह ने कल ही भाजपा की सदस्यता हासिल की थी।

लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को उतारा गया है। लखनऊ कैंट से मंत्री बृजेश पाठक को उतारा गया है। मलिहाबाद से सीटिंग विधायक जया देवी को टिकट दिया गया है। जया देवी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी हैं। लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा और लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया है। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को उतारा गया है। यहां से अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे टिकट के दावेदार माने जा रहे थे।

स्वाति सिंह की तरह अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने एक दिन पहले ही अखिलेश के खिलाफ करहल से भी उतरने की इच्छा जताई थी। इसके बाद भी न तो उन्हें करहल से उतारा गया और न ही लखनऊ पूर्व का टिकट मिल सका है।

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के हाथ भी निराशा हाथ लगी है। रीता जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ पूर्व की सीट मांग रही थीं। उन्होंने तो बेटे को टिकट के लिए सांसदी तक की सीट छोड़ने की इच्छा जता दी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिख दिया था। इसके बाद भी बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया है।

लखनऊ की सरोजनीनगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। कानपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण के बाद राजेश्वर सिंह दूसरे अफसर हैं जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। असीम अरुण को कुछ दिन पहले कन्नौज (सदर) सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है।

राजेश्वर सिंह बड़े नौकरशाही परिवार से हैं और खुद 1996 बैच के प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) अधिकारी हैं। उन्होंने 2007 में ईडी में प्रतिनियुक्ति ली थी। उन्होंने यूपी पुलिस में 10 साल और ईडी में लगभग 14 साल तक सेवा की। वह जबरन वसूली रैकेट में शामिल कई अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए जाना जाता था।

ईडी में उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदा घोटाला, अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, अमरपाली घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जैसे महत्वपूर्ण मामलों को संभाला। इस दौरान उन्होंने अपराधियों की 4000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह आईपीएस अधिकारी हैं और लखनऊ रेंज में आईजी के पद पर तैनात हैं।

दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें होगा दम : सीएम योगी

मेरठ, 01 फरवरी (एजेन्सी)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को यहां मेरठ के सिवालखास पहुंचे। यहां पर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेश हुए केंद्रीय बजट को जनता के लिए हितकर बताया है। कहा कि चुनाव से पहले लोग अलग बातें करते थे और चुनाव घोषित होने के बाद कुछ और बोलने लगे। डर के कारण प्रत्याशी बदलने लगे। दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा। किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी।

योगी ने कहा कि सुरक्षा के लिए सपा की टोपी ही खतरा है। इस लाल टोपी का रंग ही दंगा, हिस्ट्रीशीटर, राहजनी, किसानों के ट्यूबवेल से मोटर चोरी करना है। कहा कि आखिर सचिन और गौरव की क्या गलती थी, उन्होंने अपनी बहन से छेड़छाड़ का विरोध ही किया था।

मुख्यमंत्री सिवालखास से भाजपा के प्रत्याशी मनिंदरपाल सिंह का प्रचार करने यहां पहुंचे हैं। यहां से सीएम योगी किठौर के पीआरडी स्कूल प्रांगण और सिसौली पहुंचेंगे। जहां मतदाताओं से संवाद कर पार्टी प्रत्याशी सत्यवीर त्यागी के लिए वोट मांगेंगे।

योगी ने लोगों से पूछा, आपने पांच साल में कोई दंगा देखा, पहले तीसरे दिन दंगा होता था ,क्या दंगा कराने वाले को वोट देंगे। जब संकट था तब तो लड़कों की जोड़ी गायब थी, एक लखनऊ से लोगों को पिटवा रहा था, गौरव सचिन के हत्यारों को लखनऊ बुला रहा था।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाली आर्मी वाइस चीफ की कमान

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। सेना ने एक बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह सेना के उप प्रमुख (वाइस चीफ) का पदभार ग्रहण किया, जो सोमवार को सेवानिवृत्त हुए थे। उप प्रमुख का कार्यभार संभालने से पहले, पांडे कोलकाता स्थित मुख्यालय पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे।

मनोज पांडे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ पल्लनवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों की बड़े पैमाने पर आना जाना हुआ था।

इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। अपने 39 साल के सैन्य करियर में, पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, एलओसी पर इन्फेंट्री सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर-पूर्व में एक कोर की कमान संभाली है। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले वह अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

विकास और विरासत .....

हुए कहा कि इससे राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के 68 हजार करोड़ रुपये की तुलना में इस साल के बजट में 76 हजार करोड़ रुपये के लगभग की राशि आवंटित करने की बात कही गई है, इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विकास की गति में तेजी आएगी। उन्होंने इस बजट से पूर्वोत्तर राज्यों में ट्रेन, एयर, रोड और इंटरनेट सहित हर तरह की कनेक्टिविटी के बढ़ने और तेजी से विकास होने का दावा भी किया।

केंद्रीय मंत्री ने इसे प्रगतिशील बजट बताते हुए दावा किया कि उनकी सरकार बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, भविष्य के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने 2022-23 के बजट में संस्कृति मंत्रालय के लिए 13 प्रतिशत अधिक राशि के आवंटन के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बजट 100 साल में भारत के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है। विकास और विरासत साथ-साथ चलते हैं और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के लिए इस वर्ष का बजटीय आवंटन काफी अधिक रहा है।

पर्यटन मंत्रालय के .....

421.50 करोड़ रुपये प्रचार संबंधित गतिविधियों के लिए हैं। आधारभूत ढांचा विकास के आवंटित राशि में से 1181.30 करोड़ रुपये स्वदेश दर्शन योजना के लिए हैं। यह योजना मंत्रालय की मुख्य योजना है और 235 करोड़ रुपये प्रसाद योजना के लिए हैं। इसके अलावा 130 करोड़ रुपये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आवंटित हैं।

शेष आवंटित राशि को सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण, चैंपियन सर्विस सेक्टर योजना, आईटी आदि को फंड करने के लिए किया जायेगा। इसका उपयोग देश में पर्यटन मंत्रालय, इसके देश विदेश में मौजूद कार्यालयों के व्यय को पूरा करने में भी किया जायेगा।

2013-14 में पर्यटन मंत्रालय के लिए आवंटित राशि की तुलना में इस बार 76.82 प्रतिशत अधिक और गत साल की तुलना में 18.42 प्रतिशत अधिक है।

मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 227 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। आदिवासी इलाकों में पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए 98 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। चालू वित्त वर्ष में कोरोना संकट से प्रभावित सेवा क्षेत्र के ऋण गारंटी योजना शुरु की गयी है। पर्यटन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त शेयरधारक, टूर संचालक, ट्रैवेल एजेंट, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट संचालकों के लिए दस लाख तक की गारंटी के बिना ऋण और आरएलजी,आईआईटीजी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त टूरिस्ट गाइड के लिए एक लाख की ऋण सुविधा शुरु की गयी। करीब 10 वाणिज्यिक बैंकों ने यह योजना शुरू की है और कुछ लाभार्थियों को इसके तहत चेक और आवंटन पत्र भी सौंपा गया है। इस योजना के लिए मंत्रालय के बजट में 2022-23 में 12.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पांच साल के लिए इस योजना के मद में 62.5 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है : वित्त मंत्री

'केंद्रीय बैंक की ओर से जारी नहीं'

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो-करेंसी पर केंद्र के रुख को स्पष्ट करते हुए, मंगलवार को कहा कि सरकार ऐसी डिजिटल वित्तीय संपत्तियों को मान्यता नहीं देती है, क्योंकि वे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती हैं।

वित्त मंत्री के समक्ष बजट के बाद की बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाया गया, क्योंकि उन्होंने मंगलवार को संसद में अपने बजट भाषण में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरूआत करते हुए कहा था कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

इस पर सरकार का ऑष्टिकोण यह है कि डिजिटल मुद्रा अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को भी बढ़ावा देगी।

उन्होंने 2022-23 का बजट पेश करते हुए संसद में कहा कि इसलिए, ब्लॉकचैन का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने क्रिप्टो पर लगाए गए टैक्स और डिजिटल करेंसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने क्रिप्टो मुद्रा पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि करेंसी सिर्फ वह होती है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, जो इसी साल किसी समय जारी की जाएगी। क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है। उसके ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया गया है।

उन्होंने कहा, 'मैंने कहा था कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। मुद्रा केवल एक मुद्रा है, जब इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, भले

हैं कि हम उन मुद्राओं पर कर नहीं लगा रहे हैं जिन्हें अभी नियमित किया जाना है।'

अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशन तेजी से बढ़े हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में उपभोक्ता-हितैषी तरीके से पहुंचे।

मंत्री ने कहा, 'इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए और हमारी आजादी जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है।'

पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता 2022-23 में जारी रहेगी।

डिजिटल वित्तीय बैंकिंग और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, 'यह डिजिटल भुगतान को और अधिक अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।'

भारत ने स्थानीय रक्षा खरीद के लिए अलग से रखे 1.03 लाख करोड़ रुपये, रक्षा बजट भी बढ़ाया

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। भारत ने मंगलवार को निजी उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत अलग रखने के अलावा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों और प्रणालियों को खरीदने के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये (सेना के पूंजी बजट का 68 प्रतिशत) निर्धारित किया।

संसद में 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। भारत ने इस साल के बजट में सैन्य खर्च के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है। इस साल का पूंजी परिव्यय 2021-22 के बजट अनुमान से 12.8 प्रतिशत अधिक है जब यह 1.35 लाख करोड़ रुपये था।

पिछले साल के आवंटन की तुलना में कुल बजट में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत ने 2020-21 में 4.71 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 के लिए अपने बजट में सैन्य खर्च के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये अलग रखे थे। इस वर्ष का रक्षा बजट 2022-23 के लिए देश के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.03 प्रतिशत है। इसमें 2.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 1.16 करोड़ रुपये का पेंशन परिव्यय शामिल है।

बजट दस्तावेजों में संशोधित अनुमान बताते हैं कि सशस्त्र बलों ने पिछले साल के बजट आवंटन के शीर्ष पर 21,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है कि भारत ने चीन के साथ सीमा रेखा पर लंबे समय से अपना सख्त रुख अपनाया हुआ है, जिसके चलते भारत को आपातकालीन खरीद भी करनी पड़ी थी और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। पिछले साल, सशस्त्र बलों ने देश की सीमाओं पर नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हथियारों और प्रणालियों की आपातकालीन खरीद पर 20,776 करोड़ रुपये खर्च किए।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आयात को कम करने और आत्मनिर्भर्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि निजी उद्योग को एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) मॉडल के माध्यम से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य ख्रलेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रणालियों के व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल निकाय भी स्थापित किया जाएगा। उद्योग जगत ने सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के अध्यक्ष एसपी शुक्ला ने कहा कि घरेलू उद्योगों के लिए पूंजी परिव्यय निवेश को बनाए रखेगा और नई क्षमता निर्माण को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा, 'स्टार्टअप, अकादमिक और निजी उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत आवंटन एक बहुत जरूरी सुधार है।' भारत ने 70,221 करोड़ रुपए सेना के पूंजी बजट का 63 प्रतिशत पिछले साल घरेलू रक्षा खरीद के लिए, 2020-21 में 51,000 करोड़ रुपये या पूंजीगत बजट के 58 प्रतिशत की तुलना में अलग रखा है। स्वदेशी खरीद के लिए आवंटन, लगातार तीसरे वर्ष, तेजस एलसीए (हल्के लड़ाकू विमान) एमके -1 ए जेट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच), बुनियादी ट्रेनर विमान, अर्जुन एमके -1 ए टैंक, विभिन्न प्रकार की मिसाइल और अन्य हथियार खरीद को शक्ति प्रदान करेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'उत्कृष्ट बजट' पेश करने के लिए सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'यह एक ऐसा बजट है जो 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा, मांग को बढ़ावा देगा और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरे भारत के लिए क्षमता का निर्माण करेगा।'

केंद्रीय बजट बिहार के लिए निराशाजनक : उपेंद्र कुशवाहा

पटना, 01 फरवरी (का.सं.)। एनडीए घटक जनता दल-यूनाइटेड (जेडी-यू) ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पर निराशा व्यक्त की। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे 'निराशाजनक बजट' बताया।

उन्होंने कहा, 'बिहार को विशेष दर्जा देने की हमारी लंबे समय से मांग थी और उम्मीद थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर कुछ कहेंगी लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।'

उन्होंने कहा, 'केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए फायदेमंद रहा है लेकिन इसमें बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे राज्य को इसके विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।'

कुशवाहा के बयान ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान और तेज होगी।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR TEESTA MORNING
Draw No:62 DrawDate on:01/02/22
1st Prize ₹1 Crore/- 65K 37631
Cons. Prize Rs.1000/- 37631 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
00675 06032 41616 47097 52716 61933 70616 74033 86900 96122
3rd Prize ₹450/-
0106 0375 5008 5265 7012 7895 8371 9426 9567 9795
4th Prize ₹250/-
1402 1926 2070 2083 2289 4986 5123 6851 7386 8809
5th Prize ₹120/-
0004 0045 0245 0258 0377 0485 0490 0518 0710 0804
0834 1175 1460 1461 1780 1805 1905 2012 2041 2081
2164 2256 2462 2526 2734 2756 2765 2848 2883 2889
3008 3315 3350 3632 3638 3672 3900 4038 4062 4113
4237 4267 4345 4361 4400 4416 4427 4448 4605 4630
4646 4631 4697 4928 4984 5082 5301 5535 5630 5717
5995 5962 6206 6296 6323 6386 6442 6461 6676 6962
6884 7072 7287 7314 7516 7585 7620 7684 7777 7805
7939 7982 8257 8301 0323 8365 8417 8469 8494 8614
8810 8984 9023 9212 9273 9680 9688 9708 9734 9992
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR PARROT EVENING
Draw No:162 DrawDate on:01/02/22
1st Prize ₹1 Crore/- 31C 96792
Cons. Prize Rs.1000/- 96792 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
09515 14453 35079 40104 45037 57135 62663 67351 73255 90177
3rd Prize ₹450/-
0009 1695 2520 3448 4124 4956 7140 7721 8224 9744
4th Prize ₹250/-
0669 1417 2545 2752 6426 6653 7507 8654 9295 9406
5th Prize ₹120/-
0001 0153 0224 0312 0456 0522 1080 1190 1240 1429
1510 1646 1713 1727 1802 1854 1907 1916 1922 2023
2231 2290 2359 2410 2411 2658 2938 3187 3370 3432
3444 3497 3607 3639 3872 3873 3877 4160 4251 4282
4269 4321 4423 4457 4563 4617 4709 5085 5142 5359
5364 5501 5589 5620 5776 5796 5824 5917 5956 5999
6028 6056 6104 6228 6297 6419 6469 6711 6919 6975
7105 7162 7206 7276 7339 7353 7556 7585 7648 7653
7783 7930 7944 8075 8099 8253 8517 8601 8812 8900
8930 8954 8981 8982 9032 9070 9237 9458 9548 9962
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR MOON TUESDAY
Draw No:62 DrawDate on:01/02/22
1st Prize ₹1 Crore/- 85H 06145
Cons. Prize Rs.1000/- 06145 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
07937 07963 14405 33253 43948 50306 55412 59760 60528 64640
3rd Prize ₹450/-
0601 0670 2042 2533 5134 5358 5477 6009 7962 8916
4th Prize ₹250/-
1892 4094 4420 5184 5431 5539 6157 7655 8093 9086
5th Prize ₹120/-
0248 0496 0603 0746 0835 0917 0941 0962 1075 1153
1178 1208 1269 1350 1423 1675 1684 1805 1827 1866
1930 1946 2033 2266 2326 2359 2486 2660 2736 2848
2980 2923 3063 3120 3308 3450 3641 3817 3834 3850
3953 4313 4404 4438 4453 4649 4817 4917 5006 5047
5093 5313 5371 5374 5626 5636 5955 6022 6025 6128
6230 6352 6505 6619 7076 7191 7299 7423 7434 7486
7643 7676 7742 7735 7793 8003 8260 8315 8435 8514
8642 8735 8892 8971 9008 9016 9021 9143 9157 9247
9272 9335 9368 9391 9407 9499 9554 9629 9822 9870
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR 100 PARROT TUESDAY
Draw No:3 DrawDate on:01/02/22
1st Prize ₹20LAKHS/- 36170
2nd Prize ₹9000/-
0428 1658 4587 5393 5966 6858 7630 7743 9503 9932
3rd Prize ₹5000/-
1381 1444 6818 7295 7513 8164 8392 8773 9045 9074
4th Prize ₹2000/-
0696 3058 3449 5088 5812 6202 6377 6602 7414 8037
5th Prize ₹1000/-
0226 1340 2029 2093 2346 4041 4252 5688 6994 8011
6th Prize ₹500/-
0111 0310 0313 0457 0549 0786 0794 0815 0935 1009
1081 1813 1815 2172 2196 2536 2583 2643 2645 2791
3100 3135 3226 3255 3286 3312 3399 3459 3668 3821
4093 4279 4367 4414 4550 4563 4570 4659 4695 4710
4772 4782 5051 5089 5116 5122 5156 5224 5229 5238
5271 5350 5411 5480 5526 5587 5652 5897 5918 6197
6392 6477 6499 6586 6613 6655 6669 6689 6737 6877
6960 7342 7571 7744 7769 7783 7970 7979 8045 8151
8161 8350 8482 8520 8522 8530 8744 8811 9016 9124
9163 9267 9691 9710 9734 9901 9950 9962 9971 9987
ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES
Draw Time: 04:00 PM
LABHLAXMI PLATINUM TUESDAY
Draw No:3 DrawDate on:01/02/22
1st Prize ₹10,000/- 8928
2nd Prize ₹5,000/- 8714
3rd Prize ₹500/- 3965
4th Prize ₹300/- 5645
5th Prize ₹200/- 5714
6th Prize ₹100/-
0038 0067 0083 0088 0098 0106 0108 0112 0128 0145
0148 0175 0180 0183 0194 0197 0198 0262 0325 0349
0375 0411 0417 0423 0431 0458 0474 0493 0497 0510
0558 0620 0631 0656 0659 0690 0703 0715 0726 0744
0767 0786 0827 0840 0077 0899 0919 0944 1036 1039
1067 1076 1116 1149 1160 1195 1197 1257 1285 1386
1420 1455 1459 1480 1486 1506 1511 1516 1532 1538
1566 1611 1623 1676 1679 1705 1713 1739 1741 1769
1777 1791 1797 1806 1825 1833 1850 1859 1862 1872
1874 1878 1969 1992 2005 2044 2121 2127 2157 2195
2223 2281 2294 2369 2398 2429 2446 2520 2590 2597
2605 2619 2636 2715 2759 2813 2818 2859 2869 2941
2956 2976 3003 3020 3031 3052 3075 3103 3107 3113
3156 3195 3211 3228 3237 3285 3314 3365 3407 3409
3410 3485 3504 3518 3519 3522 3540 3554 3570 3575
3743 3833 3898 3903 3921 4044 4048 4049 4063 4082
4097 4107 4108 4125 4132 4143 4184 4185 4202 4394
4395 4411 4420 4514 4515 4523 4553 4605 4615 4620
4622 4630 4634 4635 4705 4747 4752 4756 4857 4862
4878 4953 5001 5031 5049 5054 5090 5104 5127 5145
5197 5208 5217 5232 5311 5338 5388 5435 5437 5491
5495 5502 5503 5520 5355 5559 5590 5599 5625 5635
5648 5658 5697 5708 5710 5712 5718 5755 5774 5817
5822 5847 5865 5882 5902 5920 5965 5977 6010 6031
6066 6078 6082 6083 6088 6095 6157 6188 6195 6196
6205 6206 6208 6275 6282 6289 6371 6384 6404 6445
6465 6492 6501 6527 6539 6545 6589 6600 6609 6615
6638 6663 6684 6691 6696 6781 6785 6844 6876 6954
6989 7900 7082 7083 7103 7129 7137 7138 7141 7161
7173 7186 7249 7264 7314 7315 7324 7327 7362 7363
7368 7405 7411 7449 7450 7457 7468 7477 7496 7522
7547 7632 7665 7698 7699 7710 7717 7725 7773 7794
7804 7808 7817 7831 7857 7935 7961 7965 7975 8043
8075 8079 8080 8124 8146 8191 8198 8252 8323 8333
8467 8493 8514 8548 8550 8562 8583 8584 8674 8702
8711 8728 8758 8759 8821 8839 8999 9011 9044 9055
9067 9089 9095 9100 9140 9213 9238 9351 9397 9489
9514 9531 9588 9604 9605 9613 9641 9660 9680 9740
9781 9816 9831 9843 9878 9941 9946 9967 9974 9976
ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES
Draw Time: 07:00 PM
LABHLAXMI TOPAZ TUESDAY
Draw No:3 DrawDate on:01/02/22
1st Prize ₹10,000/- 0798
2nd Prize ₹5,000/- 1342
3rd Prize ₹500/- 7652
4th Prize ₹300/- 7284
5th Prize ₹200/- 2689
6th Prize ₹100/-
0053 0118 0137 0154 0156 0224 0242 0248 0351 0365
0367 0400 0415 0452 0480 0521 0540 0550 0568 0681
0794 0802 0833 0907 0942 0954 0974 0998 1023 1024
1028 1043 1070 1072 1092 1110 1112 1147 1163 1179
1186 1235 1334 1405 1409 1424 1449 1463 1467 1481
1489 1499 1529 1598 1661 1697 1716 1717 1751 1757
1776 1806 1812 1843 1853 1864 1882 1889 1955 1956
2001 2033 2048 2061 2098 2101 2127 2135 2155 2162
2224 2235 2282 2338 2345 2378 2390 2394 2398 2404
2413 2419 2473 2507 2582 2630 2647 2651 2664 2686
2708 2721 2756 2774 2787 2842 2862 2911 2932 2943
2951 2992 3000 3072 3082 3091 3101 3135 3137 3155
3172 3181 3196 3234 3239 3252 3262 3267 3268 3286
3354 3376 3393 3419 3422 3437 3441 3464 3465 3510
3526 3554 3571 3583 3647 3694 3712 3716 3741 3822
3856 3877 3902 3908 3924 3928 3942 3943 3977 3986
3995 4060 4067 4090 4100 4149 4166 4195 4202 4270
4276 4320 4334 4341 4345 4366 4376 4403 4409 4416
4443 4461 4482 4551 4565 4591 4602 4665 4680 4684
4698 4701 4722 4725 4744 4755 4768 4780 4790 4822
4834 4848 4865 4866 4871 4943 4947 4961 4996 5003
5006 5027 5076 5086 5087 5090 5157 5175 5194 5197
5229 5238 5266 5207 5314 5322 5456 5472 5540 5551
5555 5574 5581 5583 5599 5634 5674 5715 5766 5779
5798 5818 5893 5936 5974 6097 6190 6228 6308 6327
6378 6385 6437 6481 6497 6512 6520 6534 6603 6631
6632 6639 6675 6706 6754 6782 6822 6829 6847 6851
6953 6663 6937 6953 6956 6976 6977 6982 6989 7045
7110 7123 7172 7188 7191 7201 7247 7300 7307 7341
7371 7440 7443 7485 7507 7524 7529 7574 7596 7607
7615 7627 7662 7748 7751 7757 7781 7782 7811 7812
7872 7886 7889 7893 7916 7963 7968 7991 7992 7993
7999 8032 8060 8085 8091 8097 8109 8125 8179 8207
8235 8319 8329 8360 8376 8394 8400 8403 8476 8482
8483 8607 8631 8722 8730 8740 8778 8783 8788 8800
8809 8848 8852 8858 8859 8875 8878 9013 9021 9028
9030 9047 9063 9152 9176 9180 9223 9292 9332 9409
9467 9497 9504 9518 9549 9555 9578 9590 9598 9631
9655 9693 9699 9724 9762 9800 9806 9828 9919 9925
ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES,
GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

चुनौतियों की कसौटी पर

हर दौर की जरूरत अलग होती है। सालाना बजट को परखने की कसौटी यही होती है कि वह अपने समय की जरूरतों और आने वाली चुनौतियों से किस तरह दो-चार होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का जो बजट संसद में पेश किया है, उसकी समीक्षा भी इसी कसौटी पर हो सकती है। महामारी के दौर ने जो परेशानियां खड़ी की हैं, सीमित संसाधनों के जरिये उनसे निपटना किसी भी वित्त मंत्री के लिए टेढ़ी खीर हो सकता था। खासकर इसलिए कि अब यह मामला सिर्फ जन-स्वास्थ्य का नहीं है। महामारी ने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान कई सारे उद्योग बंद हुए हैं, उत्पादन कम हुआ है, लोग बेरोजगार हुए हैं, आर्थिक असमानता और गरीबी, दोनों में इजाफा हुआ है। इन हालात में वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट देने की कोशिश की है, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करे।

पिछले कुछ समय से अर्थशास्त्री दो जरूरतों की ओर ध्यान खींच रहे थे। एक तो रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, और दूसरी, ऐसे तरीके अपनाने पर, जिनसे लोगों और खासकर मध्यवर्ग की जेब में ज्यादा पैसा जाए और इस पैसे से जब वे बाजार में कुछ खरीदने निकलें, तो मांग बढे.। वित्त मंत्री ने पहली जरूरत पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया। रोजगार का मामला मध्यवर्ग की आमदनी बढ़ने से कहीं बड़ा है। खासकर देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से रोजगार को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। इसके लिए बजट में सबसे ज्यादा जिसकी बात की गई है, वह है पूंजीगत खर्च। सरकार अगर बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण करती है, तो इनमें अकुशल से कुशल तक कई श्रेणियों में लोगों को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर लघु और मध्यम उद्योगों में पैदा होते हैं। महामारी के दौरान ये उद्योग ही सबसे ज्यादा बंद हुए। बजट में ऐसे उद्योगों के लिए आपातकालिक कर्ज की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, जो उन्हें संकट से उबार सकती है। मुमकिन है, आयकर दरों में कोई बदलाव न होने की वजह से मध्यवर्ग इस बजट से कुछ निराश हो, लेकिन संभव है कि कर व्यवस्था में स्थायित्व के लिए शायद सरकार को यह जरूरी लगा हो।

एक आशंका यह थी कि देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते बजट पर चुनावी असर दिख सकता है। वित्त मंत्री बजट को इस प्रभाव से मुक्त रखने में सफल रहीं और उन्होंने लोक-लुभावन घोषणाओं का ढेर नहीं लगाया। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें तात्कालिकता के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

यही वजह है कि इसमें कई जगह हरित अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, प्राकृतिक खेती जैसे शब्द सुनाई देते हैं। बजट 5जी तकनीक के जल्द आगमन को लेकर भी आश्वस्त करता है और पूरी तरह डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर भी। इस बजट का सबसे चिंताजनक पहलू है महंगाई की आशंका। चालू वित्त-वर्ष में वित्तीय घाटा 6.9 फीसदी तक पहुंच गया है, अगले वित्त-वर्ष के लिए 6.4 प्रतिशत का अनुमान है। अगले पूरे साल में सरकार को एक तो यह प्रयास करना होगा कि यह घाटा इस अनुमान से ज्यादा न बढ़े और दूसरे मुद्रास्फीति के रूप में इस घाटे की मार समाज के गरीब तबके पर न पड़े।

उम्मीदों को साकार करने का अवसर

नारायण कृष्णमूर्ति

बहुत पुरानी बात नहीं है, जब वित्तमंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाते वक्त सड़कें सूनी पड़ जाती थीं और लोग टीवी सेट से चिपके रहते थे। लेकिन यह सब कुछ पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। मसलन, रेल बजट जहां पूरी तरह खत्म हो गया है, वहीं बजट सरकार के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने का एकमात्र अवसर नहीं रह गया है। हाल के वर्षों में बजट भाषण एक विजन डॉक्यूमेंट बन गया है और बजट आवंटन सिर्फ आने वाले वर्ष के लिए नहीं, बल्कि तीन से पांच साल की समय सीमा के लिए किया जा रहा है।

बजट में कई ऐसी घोषणाएं होती हैं, जिसमें नियोजित व्यय के लिए धन आवंटित किए जाते हैं, लेकिन आवंटन का विवरण संबंधित मंत्रालयों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में, कोविड के कहर ढाने से बहुत पहले सरकार ने 111 लाख करोड़ रुपये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए आवंटित किए थे, जिसे बाद में संशोधित कर वर्ष 2025 तक पांच वर्षों के लिए 145 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पाइपलाइन में अभी तक इस फंड का सिर्फ पांच फीसदी ही इस्तेमाल हुआ है।

इसी तरह अगस्त, 2021 में, बजट के महीनों बाद, सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा की, जिसके तहत चार साल की अवधि में यानी वित्त वर्ष 2025 तक सरकार की परिचालन संपत्ति का मौद्रीकरण कर छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। हालांकि यह घोषणा सरकार के बजट खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराने को सही ठहराती है, लेकिन वर्षों से ऐसे लक्ष्य केवल लक्ष्य बनकर रह गए हैं और कई बार इनमें समय सीमा की चूक हुई है।

वर्ष 2015 में जब 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत हुई थी, तब इसे लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़े बदलाव लाने वाला माना गया था। इस योजना के प्रचार ने कई भारतीयों को विश्वास दिलाया होगा कि यह समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। लेकिन हाल ही में लोकसभा में महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट से पता चला कि इस योजना के लिए आवंटित 80 फीसदी धनराशि केवल प्रचार पर खर्च की गई!

समिति ने पाया कि वर्ष 2016-2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपये में से 78.91 प्रतिशत केवल मीडिया विज्ञापन पर ही खर्च कर दिए गए। ऐसी कई योजनाएं हैं, जिनकी घोषणा की जाती है, इनके लिए धन आवंटित किया जाता है, लेकिन वास्तविकता की जांच करने पर बाद में यह पता चलता है कि परियोजनाओं को वस्तुत: वास्तविक कार्य के लिए धन ही नहीं मिला है। कुछ मामलों में लक्ष्य इतने महत्वाकांक्षी थे कि आवंटित धन वास्तव में विकास के लिए अपर्याप्त साबित हुए।

ऐसे समय में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अस्थिर है और बढ़ती भूख, घटते रोजगार सृजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बदहाली और दरकते शिक्षा तंत्र पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है, वर्ष 2022 का बजट एक ऐसे राष्ट्र की उम्मीदों को साकार करने का अवसर हो सकता है, जो सभी मोर्चों पर चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब तभी संभव है, जब बजट सार्वजनिक खर्च बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे और इस प्रक्रिया में अपने दायरे में लोगों को रोजगार दे, जहां रिक्तियों को भरने और सभी वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करने की जरूरत है।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 2019 में कॉरपोरेट जगत को जो कर लाभ दिया गया था, उसने वास्तव में क्षमता निर्माण या रोजगार सृजन में कोई मदद नहीं की, ऐसे में, कॉरपोरेट इंडिया पर टैक्स लगाना बुरा विचार नहीं है। इसी तरह, सरकार की राजकोषीय नीति कमजोर है-सिर्फ यही नहीं कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का दोगुना होकर 9.2 फीसदी हो गया, बल्कि दो साल की कोविड महामारी के कारण सरकार को अब कई बार दूसरी संस्थाओं के जरिये भी कर्ज लेना पड़ रहा है। यह नियोजित खर्च से बाहर का उधार होता है, जिसे बाद में बजट में शामिल किया जाता है। इस तरह यह सरकार के बजट के हिसाब पर असर डालता है।

आम आदमी के लिए बजट ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। आयकर से संबंधित बजट घोषणाओं की बहुत प्रतीक्षा की जाती है, लेकिन इस मोर्चे पर छूट की बहुत संभावना नहीं है। दो साल पहले नई कर प्रणाली की घोषणा की गई, लेकिन कोई भी इस नई प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि यह कर बचत का अवसर प्रदान नहीं करती, आम आदमी जिसे जबरन बचत और निवेश के रूप में देखता है, यह उसका एक अभिन्न अंग है।

इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ बदलती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में वित्तमंत्री द्वारा समय-समय पर की गई बजट-जैसी कई छोटी घोषणाओं ने भी केंद्रीय बजट के महत्व को कम कर दिया है। बजट को समझने का एक आसान तरीका यह है कि सरकार के राजस्व और उसके खर्चों और घाटे का विवरण देने वाले आंकड़ों को देखा जाए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 ने सरकार के लिए अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार करने और राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

इस अधिनियम ने सरकार के सामने राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके अनुसार, सरकार को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक लाना था। यह एक ऐसी समय सीमा है, जो कोविड महामारी के कारण चूक गई लगती है। साथ ही, अधिनियम के अनुसार, सरकार के ऋण को 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद के 40 फीसदी तक सीमित किया जाना है, जो एक कठिन कार्य की तरह दिखता है।

घर, व्यवसाय या सरकार के लिए बजट प्रबंधन हमेशा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें चुनने के लिए कई विकल्प होते हैं, पर सही निर्णय लेना कठिन नहीं होता। लेकिन सरकार की उधारी को परतों में छिपाकर और तीन से पांच वर्षों के लिए नियोजित खर्च कर केवल नियोजित बजट से दूर जाने की गुंजाइश ही बढ़ती है। इस तरह से संपूर्ण बजटीय कवायद को टेलीविजन पर केवल तमाशा ही बनाया जा सकता है, जो तत्काल सकारात्मक बदलाव को शायद ही संभव कर पाए।

कोविड ने बढ़ाई वित्तमंत्री की चुनौती

केएस तोमर

महामारी के कारण पिछले दो सालों से अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर पर पड़े नकारात्मक प्रभाव के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिसमें उन्हें सबसे बुरी तरह से प्रभावित लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती होगी। विश्लेषकों का मानना है कि अमीरों को सख्त कर अनुपालन के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, ताकि संसाधन जुटाए जा सकें।

वित्तमंत्री यदि करों में वृद्धि करती हैं, तो इसके लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैयार रहना चाहिए, ताकि महामारी से सर्वाधिक पीड़ित लोगों के लिए आवंटन बढ़ाया जा सके। सरकार को 6.8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य हासिल करने में कर राजस्व मददगार हो सकता है।

कर राजस्व सरकार का कुछ दबाव कम करेगा, ताकि वह स्वतंत्र होकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक फंड जारी कर सके, गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन के कार्यक्रम को जारी रख सके और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर तीन महीने में दी जाने वाली मदद जारी रखी जा सके।

जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निरंतरता की जरूरत है, लेकिन उसकी राह में कुछ खास तरह की अड़चनें हैं। सरकार इसके तहत कई क्षेत्रों को कवर करने और सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश करेगी। सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए बड़े विनिर्माण क्षेत्र पर और विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र को अनिवार्य मदद की जरूरत है, ताकि निजी खपत में वृद्धि हो सके। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण उनमें गंभीर रूप से बाधा आई है। उन्हें कामकाजी पूंजी के साथ ही ऋण की सुविधाओं की जरूरत है। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को आगे बढ़ा सकती है।

एमएसएमई को महामारी के अलावा 2016 में नोटबंदी और 2017 में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण भी नुकसान हुआ, लेकिन यदि बाधाएं दूर कर दी जाएं, तो यह क्षेत्र भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है। महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ऐसे में वित्तमंत्री ने अतार्किक तरीके से आवंटन को 2020-21 के 99,311 करोड़ रुपये से घटाकर 2021-22 के बजट में 93,223 करोड़ रुपये कर दिया था।

महामारी के दो वर्षों में ऑनलाइन कक्षाओं ने गरीब छात्रों, विशेष रूप से बिना इंटरनेट की सुविधा वाले गांवों और डिजिटल पहुंच रखने वाले संपन्न वर्ग के बीच शिक्षा की पहुंच का अंतर बढ़ाया है। इसमें सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो यह युवाओं की एक पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने की जरूरत है, जो कि 2020-21 में 3.5 फीसदी से बढ़कर सात फीसदी हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बावजूद वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर नौ फसदी रह सकती है और वर्ष 2023-24 में 7.1 फीसदी रह सकती है, यह महामारी को देखते हुए बुरी खबर नहीं है।

शहरी गरीब भी महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लिहाजा बजट में उनके लिए नई रोजगार गारंटी योजना की उम्मीद की जा सकती है। ध्यान रहे, पिछले दशक में गरीबों की संख्या में कमी आई थी और यह 2011 में 34 करोड़ से घटकर 2019 में 7.8 करोड़ रह गए। लेकिन कोविड-19 महामारी के दो सालों की अवधि में गरीबों की संख्या 13.4 करोड़ बढ़ गई और गरीबों की कुल संख्या 21 करोड़ हो गई।

सीएमआईई की रिपोर्ट दिखाती है कि बेरोजगारी दर 6.5 फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी हो गई और शहरी क्षेत्र में 2021 में यह आंकड़ा 9.3 फीसदी था। जाहिर है, रोजगार पैदा करने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जिस पर वित्तमंत्री को निश्चित रूप से गौर करना चाहिए।

रोगजगार संग आत्मनिर्भरता की चुनौती

अश्विनी महाजन

पिछले लगभग दो वर्षों से कोविड महामारी से ग्रस्त अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, एक ओर सरकारी खजाने से गरीब जनता के लिए राहत, तो दूसरी ओर राजस्व की कमी से जूझते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के लिए अपना चौथा वार्षिक बजट बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया अनुमानों के अनुसार, 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की वृद्धि दर नौ प्रतिशत रही और आगे आने वाले दो वर्षों में भी यह दर नौ प्रतिशत से कम रहने वाली नहीं हैं।

जीडीपी ग्रोथ की यह अनुकूल स्थिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की प्राप्तियों में परिलक्षित हो रही है। कोरोना काल के दौरान आमदनी से अधिक खर्चे की कुछ भरपाई तो इन करों से हो जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए अभी बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने की चुनौती वित्तमंत्री के सामने रहेगी। पिछले लगभग 20-22 वर्षों में विदेशों, खासतौर पर चीन पर निर्भरता के कारण देश की मैन्यूफैक्चरिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा से यह आशा बंधी है कि विदेशों पर निर्भरता कम करते हुए मैन्यूफैक्चरिंग में देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। वित्तमंत्री ने अपने पिछले बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाले कुछ वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की थी।

मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के हिसाब से वित्तमंत्री को बजट में बड़े आवंटन करने की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में देश किसान आंदोलन की बड़ी त्रासदी से गुजरा है।हालांकि नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन का पटाक्षेप हो गया है, पर देश में खेती-किसानी की हालत को सुधारने की आवश्यकता रेखांकित हुई है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की अपने गांवों में वापसी के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गांवों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वहां कृषि से संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ कारीगरी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने की भी जरूरत महसूस की जा रही है। मुर्गीपालन, पशुपालन, डेयरी, मशरूम फार्मिंग, मछली-पालन, ग्रामोद्योग सरीखे रोजगार इसकी पूर्ति कर सकते हैं।

इन सब कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बजट में आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। आज देश खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और दालों में भी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। लेकिन अब भी खाद्य तेलों के लिए देश विदेशों पर निर्भर है। खाद्यान्नों का जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, जिसके चलते आज फसल चक्र में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान की जरूरत होगी। कोरोना से पूर्व आर्थिक गिरावट और कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों में रुकावट के चलते रोजगार सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। रोजगार को बजट में महत्व मिलना अपेक्षित ही नहीं, जरूरी भी है।

लगभग एक हजार उत्पादों की, जो पहले लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे, सूची घटते-घटते शून्य पर आ गई। इसके कारण लघु उद्योगों का पतन तो हुआ ही, आयातों पर हमारी निर्भरता भी बढ़ी और रोजगार का भी ह्रास हुआ। लघु उद्योगों के आरक्षण की उस नीति को बहाल करने की जरूरत होगी। साथ ही लघु व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उसके पूंजी निवेश में 25 प्रतिशत की सब्सिड़ी सहायक हो सकती है। मनरेगा को यदि कृषि और लघु उद्योगों के लिए विस्तारित किया जाए, तो ग्रामीण युवाओं को लंबे समय तक और अधिक लाभकारी रोजगार मिलने के रास्ते खुलेंगे।

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा यह आह्वान किया गया है कि देश के उद्यमों एवं स्टार्ट-अप्स को देश में ही पूंजी मिले। इसके लिए जरूरी है कि विदेशी निवेशकों को जो करों में छूट मिलती है, वह छूट देशी निवेशकों को भी मिले। सरकार को अपनी कर प्रणाली को दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि स्टार्ट-अप्स को ज्यादा निवेश मिले और देशी निवेशकों को ज्यादा अवसर।

हमेशा गैर-जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं राहुल : सीतारमण

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बजट जीरो है और इसमें कुछ नहीं है। इस पर अब सीतारमण ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल को बजट की समझ ही नहीं है, उन्हें पहले इसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल हमेशा गैर-जिम्मेदार टिप्पणियां करते हैं और उन्होंने बिना होमवर्क किए बजट पर टिप्पणी की है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'मुझे उन लोगों पर दया आती है, जो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। केवल इसलिए कि आप ट्विटर पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, यह आपके काम नहीं आएगा। पहले उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ करना चाहिए और तब इसके बाद इसके बारे में बोलना चाहिए।'

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था, 'मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है।'

कांग्रेस पार्टी ने आलोचना करते हुए कहा है कि बजट में गरीब, किसान और बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में सिर्फ जुमले हैं। मोदी सरकार ने देशवासियों की उम्मीदों को झटका दिया, बजट वेतनभोगी और मध्यमवर्ग की उम्मीदों को झटका है। कोरोना काल में वेतन कटौती और कमरतोड़ महंगाई झेल रहे मध्यमवर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर कहा कि ये गरीब को और गरीब बनाने और रोजगार छीनने वाला बजट है।

राहुल के ट्वीट और कांग्रेस की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस नाजुक अर्थव्यवस्था को उन्होंने (कांग्रेस) पीछे छोड़ दिया है, उसे पुनर्जीवित करना एक कठिन काम रहा है। महामारी के समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रोत्साहन पैकेजों में इतना देने के बाद हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बिना सोचे-समझे इस तरह की टिप्पणी करने पर तो मुझे केवल उस पार्टी पर दया आ सकती है, जिसके पास एक ऐसा नेता है, जो बिना सोचे समझे टिप्पणी करता है।'

सीतारमण ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि जो वह हमसे कह रहे हैं, उस पर खुद अमल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। कुछ राज्यों में उनकी भी सरकारें हैं। उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या पंजाब में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है? क्या महाराष्ट्र में किसान अच्छा कर रहे हैं? महाराष्ट्र में अब भी कपास किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने इसे क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा, 'उनको पहले उन राज्यों की फिक्र करनी चाहिए, जहां उनकी पार्टी का शासन है। वो उन योजनाओं को लागू करें, जिनकी घोषणा केंद्र ने की है। वो पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पर ध्यान दें।'

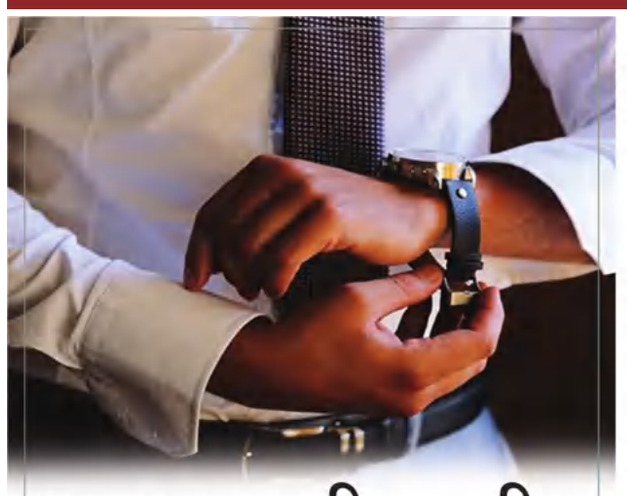

क्या आप भी जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं ? ये हैं फायदे एवं नुकसान

एक तो लोगों को नौकरी मिलना आज के समय में बेहद मुश्किल का कार्य है, वहीं कई लोग भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें एक नौकरी छोड़ने से पहले ही दूसरी नौकरी मिल जाए! ऐसे में थोड़ी ग्रोथ के लिए लोगबाग जल्दी-जल्दी नौकरी चेंज करने लगते हैं। शायद आप भी उनमें से हों, किन्तु अगर आप भी जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करते हैं तो यह जान लें कि शार्ट टर्म में बेशक इसके कुछ फायदे दिखें, किन्तु दीर्घावधि में इसका काफी नुक्सान होता है।

हालांकि अभी के समय में हालात यह हैं कि अब पहले की तरह लोग एक ही नौकरी पर बहुत दिन तक कार्य नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी चेंज करने में वह अपनी ग्रोथ देखते हैं, और उसी अनुरूप डिसीजन भी लेते हैं।

किंतु जॉब बदलने का फैसला कुछ मामलों में बेशक ठीक लगता है, किंतु कुछ मामलों में यह कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आइये जानते हैं अगर फायदे की बात करें तो आप यह जान लीजिए कि जॉब बदलने में सबसे पहले तो कुछ परसेंट ही सही, मगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके काम के अधिक से अधिक पैसे मिलें, और एक नौकरी में अगर उस अनुरूप ग्रोथ नहीं होती है, तो वह जॉब बदलना चाहता है, और ऐसे में उसे तुरंत ही ग्रोथ मिल जाती है।

वहीं अगर दूसरे फायदे की बात करें तो इससे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका नेटवर्क बेहतर होता है। अगर एक कंपनी में आप जॉब करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, और इस तरीके से अलग-अलग कंपनी में आपका बेस तैयार होता चला जाता है।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कंपनी में काम करने पर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपकी स्किल कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाती है, तो दूसरी कंपनी में जब आप जाते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है। चाहे वहां आपका नया सीनियर हो, चाहे वहां का इनवायरमेंट हो, आप उस कंपनी से नई चीजें जरूर सीखते हैं, और यह वह चीज है जो आपको आने वाले दिनों में मजबूती करती है। इसके अलावा कई भारत लोग एक जगह पर कार्य करने से बोर भी हो जाते हैं, ऐसे में नयी जॉब में उन्हें नयापन भी मिलता है।

हालांकि यह इसका पॉजिटिव पक्ष है, किंतु कुछ निगेटिव पक्ष भी हैं, जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

नुकसान की बात करें तो बार बार जॉब चेंज करने से पोजीशन के मामले में आपके आगे बढ़ने पर असर पड़ सकता है। जी हाँ! एक ही कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो वहां आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होती है। वहां आपको प्रमोशन मिलता रहता है, किंतु जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो सीनियर पोजिशन पर आपको पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है।

इससे आपकी लॉयल्टी भी चेक की जाती है। अगर आप कुछ ज्यादा ही जॉब चेंज करते हैं, तब आपको किसी हायर पोजिशन पर जॉब देने से एचआर मैनेजर निश्चित ही कई बार सोचेगा।

कंपनी अगर किसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आप की हायरिंग कर भी लेती है, तो भी कंपनी श्योर नहीं हो पाती है कि आप आखिर कितने दिन जॉब करेंगे? कहीं आप बीच में ही जॉब छोड़ कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे? ऐसे में आप शक के घेरे में आ जाते हैं!

यह कार्य सिर्फ पोजीशन के मामले में ही नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के मामले में भी है, तो क्लाइंट इंटरेक्शन के मामले में भी है। जब तक आप किसी कंपनी के लम्बे समय तक वफादार नहीं होते हैं, तब तक किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमांड आपके हाथ में देने से निश्चित रूप से वह कंपनी हिचकिचाएगी। इसी प्रकार से बड़े क्लाइंट हैंडलिंग में भी कंपनी आपको तब तक इंवॉल्व नहीं करेगी, जब तक आप उसके प्रति लॉयल साबित न हो जाएँ! ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाओं से आपके दूर रहने की शुरुआत हो जाती है।

कंपनी बार-बार चेंज करने का आपके फाइनेंसियल पोजीशन पर भी खासा असर पड़ता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप होम लोन या दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें.आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर चेक की जाती है। आप किस कंपनी में कितने लंबे समय तक रहे हैं, यह आपके लिए एक प्लस प्वाइंट साबित होता है। वहीं अगर आप बार-बार अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप की फाइनेंसियल स्टेबिलिटी पर एक सवाल खड़ा होता है।

मैनेजेरियल स्किल डेवलपमेंट पर पड़ता है फर्क

जी हां! ऊपर से आपको बेशक लगे कि आप कुछ चीजें ऊपर ऊपर समझ गए हैं, किंतु प्रबंधन के गुणों को आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक आप किसी कंपनी में देर तक नहीं टिकेंगे! कहीं टिक कर काम करने के बाद ही कंपनी पॉलिटिक्स, प्रबंधन टेक्निक आप समझ पाते हैं। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस प्रकार लेती है, वास्तव में उसकी रुचि और भविष्य की योजनायें क्या हैं, यह आप गहराई से एक समय के बाद ही समझ पाते हैं। अगर बाद में आप कभी अपना उद्यम शुरू करना चाहें, तो इसलिए जरूरी है कि किसी कंपनी में आप देर तक टिक कर काम करें, अन्यथा आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे।

पॉलीमर साइंस में बीटेक करने के बाद है शानदार करियर संभावनाएं

विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलीमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं।

मौजूदा तकनीकी दौर में पॉलीमर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इनमें प्लास्टिक, मोल्डेड सामग्री, सिंथेटिक फाइबर, रबर आदि शामिल हैं। ईको-फ्रेंडली और रीसाइक्लेबल प्लास्टिक के साथ इन सभी पॉलीमर प्रोडक्ट्स के उचित प्रबंधन की आवश्यकता भी समय के साथ बढ़ रही है। यह काम पॉलिमर इंजीनियर्स करते हैं। वे प्लांट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन और थर्मोडाइनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलीमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं। आज के इस लेख में हम आपको पॉलीमर साइंस में बीटेक के बाद करियर अवसर के बारे में जानकारी देंगे-

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के अवसर

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद आप सरकारी फर्मों जैसे सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला और सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में बतौर जूनियर रिसर्च फेलो काम कर सकते हैं। इन फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कम से कम 55% अंकों के साथ एम.टेक डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई भी नेट के लिए बैठ सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी बी टेक डिग्री में 60% अंक प्राप्त किए हैं, वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में 40,000/- रुपये के मासिक वेतन के साथ काम कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी वैज्ञानिक बी पद की भूमिका में पॉलिमर इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती करता है। इनके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) जैसे संगठन भी पॉलिमर इंजीनियरिंग में बी टेक स्नातकों को नियुक्त करते हैं। इनके अलावा स्नातक डिग्री धारक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑयल इंडिया लेबोरेटरीज, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग प्लांट्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओएनजीसी) आदि विभागों में भी रोजगार पा सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में लेक्चरर पद का विकल्प भी चुन सकते हैं।

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद निजी क्षेत्र के अवसर

जर्मन आधारित कंपनी विंडमोलर एंड होल्शर, अक्सर अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुभाग में संचालन करने के लिए पॉलिमर इंजीनियरों की भर्ती करती है। 7 से 8 साल के कार्य अनुभव वाले लोग एलाइड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स/बिजनेस डेवलपमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आप 35,000/- से रु।50,000/- प्रति माह तक की सैलरी पा सकते हैं। अपोलो टायर्स लिमिटेड, सिएट लिमिटेड आदि जैसी टायर कंपनियों को भी पॉलिमर इंजीनियर्स की जरूरत है। पॉलीमर इंजीनियरिंग में स्नातकों के लिए क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स/ टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलीमर स्पेशलिस्ट आदि सामान्य जॉब प्रोफाइल हैं।

प्रतिभावान विद्यार्थियों को तराशती योजना

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

नेशनल टेलेंट सर्च यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनसीईआरटी की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना और उनकी प्रतिभा को बढ़ाना है। इसके तहत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन और विधि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना प्रतिभावान विद्यार्थियों को मासिक स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक मदद दे कर सहयोग देती है। इस योजना में बेसिक साइंस, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के लिए पीएचडी स्तर तक सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन एवं विधि के लिए पीजी स्तर तक सहायता दी जाती है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कक्षा 8 स्तर पर किया जाता है।

स्कॉलरशिप

परीक्षा आयोजन के आधार पर कक्षा 8 की परीक्षाओं के लिए बैठे छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए 1000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं।

स्कॉलरशिप की राशि प्रत्येक माह 500 रुपए होती है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत और विकलांग छात्रों के लिए 3 प्रतिशत स्कॉलरशिप आरक्षित होती है। स्कॉलरशिप का भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता को न देकर संबद्ध संस्थान के प्रमुख के माध्यम से दिया जाता है।

चयन प्रक्रिया

प्रतिभाओं की पहचान दो स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है। प्रथम स्तर का चयन अलग-अलग राज्य/यूनियन टेरेटरीज द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रथम स्तर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही एनसीईआरटी द्वारा संचालित द्वितीय स्तर की परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। राज्य और यूनियन टेरेटरीज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा के साथ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की भी परीक्षा आयोजित करते हैं।

पात्रता

मान्यताप्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी उस राज्य/यूनियन टेरेटरी द्वारा संचालित प्रथम स्तर की परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं, जिस राज्य में विद्यालय स्थित है।

आवेदन प्रपत्र

आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने के लिये राज्य संपर्क अधिकारी से संपर्क करें। आवेदन-प्रपत्र एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन प्रपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तथा प्रपत्र कहां जमा कराया जायेगा, इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के संपर्क अधिकारी से पता किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों की आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां भिन्न हो सकती हैं।

शुल्क

एनसीईआरटी द्वारा द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। राज्य और यूनियन टेरेटरी प्रथम परीक्षा के लिए अपेक्षित शुल्क के भुगतान के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसलिये आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले कितनी और कैसे फीस दी जायेगी, इसका पता अपने राज्य संपर्क अधिकारी से लगा लेना चाहिए।

परीक्षा माध्यम

परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी के साथ असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में संचालित की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में जिस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उस विकल्प का उल्लेख करें। इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को उस भाषा में प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षा-विधि

8वीं के लिए लिखित परीक्षा की विधि इस प्रकार है - प्रथम स्तर की राज्य/ यूनियन टेरेटरी स्तर पर संचालित परीक्षा में दो भाग होंगे (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी)। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परीक्षा में (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी) शामिल होंगे। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। (स) इंटरव्यू - इंटरव्यू के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में प्रथम भाग एमएटी और द्वितीय भाग एसएटी शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएं एक छोटे से अंतराल पर अलग-अलग ली जाएंगी। मानसिक योग्यता परीक्षा- एमएटी - चार विकल्पों सहित इसमें 90 मल्टीच्वॉइस प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। समय 90 मिनट होगा।

स्कॉलरशिप पाने की सामान्य शर्तें

स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो। वह अच्छा आचरण बनाए रखता हो (संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित) और अपना अध्ययन एक नियमित विद्यार्थी के रूप में कर रहा हो। बिना उचित अवकाश के अनुपस्थित न होता हो। पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करता हो। कोई रोजगार नहीं करता हो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना पीएचडी कोर्स को छोड़ कर छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोई अन्य स्कॉलरशिप स्वीकार करने से वंचित नहीं करती, अलबत्ता किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विदेश में अध्ययन के लिए कोई स्कॉलरशिप उपलब्ध नहीं होगी। यदि कोई प्राप्तकर्ता पंजीकरण/प्रवेश के एक माह के अंदर अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ता है तो उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी।

विजुअल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र में हैं अपार संभावनाएं

विजुअल मर्चेंडाइजिंग शब्द भले ही कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन सेल्स और एडवरटाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोग इससे भली-भांति वाकिफ हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग वास्तव में एक आर्ट है, जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रॉडक्ट या सर्विस को क्लाइंट्स के सामने कुछ इस तरह पेश करता है ताकि वह सेल्स को बढ़ावा दे सके। अब इस कॉन्सेप्ट को रिटेल सेक्टर में एक मार्केटिंग टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वह सभी गतिविधियां शामिल हैं, जो रिटेल स्टोर्स में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रॉडक्ट के संभावित ग्राहकों के माइंड को समझना और उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में शिक्षित करना व प्रॉडक्ट को बेहद इफेक्ट व क्रिएटिव तरीके से पेश करना आदि। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस करियर के बारे में

क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग

एजुकेशन एक्सपर्ट बताते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विजुअल मर्चेंडाइजर कहा जाता है। विजुअल मर्चेंडाइजर ऐसे पेशेवर हैं जो किसी भी ब्रांड, एक चेहरे को देने के लिए जिम्मेदार हैं। वे ऑनलाइन शॉपर्स और रिटेल स्टोर दोनों के लिए विंडो और स्टोर डिस्प्ले में अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं। वे स्टोर थीम की योजना बनाते हैं, डिस्प्ले के लिए प्रॉपर की व्यवस्था करते हैं, डिस्प्ले फिक्स्चर और लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं, ओपनिंग से पहले स्टोर सेट करते हैं, फ़्लोर प्लान के साथ काम करते हैं और डिस्प्ले को बनाने के लिए सेल्स फ़्लोर पर स्टोर कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। एक विजुअल मर्चेंडाइजर का मुख्य उद्देश्य स्टोर की छवि के अनुरूप डिस्प्ले बनाना और अधिक ग्राहकों को स्टोर में लाना है।

शैक्षणिक योग्यता

आजकल ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग से संबंधित सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स को करने के लिए छात्र का 12वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि अधिकतर जगहों पर विजुअल मर्चेंडाइजिंग को फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है।

कॅरियर एक्सपर्ट के अनुसार, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के कोर्स में छात्रों को विजुअल मर्चेंडाइजिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है जैसे कि रिटेल स्टोर का लेआउट और डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, स्टोर के अंदर फर्नीचर और फिक्स्चर की स्थापना, स्टोर डिस्प्ले और उत्पादों की प्रस्तुति, विभिन्न संचार साधनों के उपयोग के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करना।

व्यक्तिगत गुण

इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों में डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के गुण का होना बेहद आवश्यक है। एक विजुअल मर्चेंडाइजर में बेहतरीन आर्गेनाइजिंग स्किल्स होने के साथ-साथ प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व टाइम मैनेजमेंट आदि विशेषताएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें संचार व इंटरपर्सनल स्किल्स, समस्या सुलझाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजर को उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को जानना आना चाहिए और उसे रूझानों का भी पूर्वानमान लगा लेना चाहिए।

संभावनाएं

शॉपिंग मॉल, फाइव स्टार होटल, बुटीक व रिटेल आउटलेट्स की संख्या बढ़ने के साथ ही विजुअल मर्चेंडाइजर्स की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। विजुअल मर्चेंडाइजर फैशन बुटीक, शॉपिंग मॉल, एम्पोरिया, डिजाइन कंपनी, आर्किटेक्चर फर्म, थीम पार्टी ऑर्गनाइजिंग कंपनी आदि में जॉब कर सकते हैं। वे प्रदर्शनियों, मेलों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अवार्ड सेरेमनी, मॉल, रिटेल में विंडो डिस्प्ले के लिए अनुबंध के आधार पर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में एक फ्रेशर भी दस से पंद्रह हजार आसानी से कमा सकता है। वहीं कुछ समय के अनुभव के बाद आप किसी बड़े ब्रांड के रिटेल आउटलिट में काम कर सकते हैं और एक आकर्षक पैकेज पा सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बैंगलोर
- द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई
- स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कोच्चि
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा

समाचार

91 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल, देश में टिकाव

नईदिल्ली । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उबाल के बावजूद घरेलू स्तर पर आज लगातार 88 वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच और 10 रुपये घटाने की घोषणा के बाद 4 नवंबर 2021 को ईधन की कीमतों में तेजी से कमी आई थी। इसके बाद राज्य सरकार के मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने के फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में भी वैट को कम करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राजधानी में 02 दिसंबर 2021 को पेट्रोल लगभग आठ रुपये सस्ता हुआ था। डीजल की भी कीमतें हालांकि जस की तस बनी रहीं। सप्ताहा के पहले दिन आज सिंगापुर में लंदन ब्रेंट क्रूड 1.10 प्रतिशत की बढ़त लेकर 91.02 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 1.08 प्रतिशत बढ़कर 87.76 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) कम कर दिया था, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिली थी। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की नित्य प्रतिदिन समीक्षा होती है और उसके आधार पर प्रतिदिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

1 फरवरी से बैंकिंग रूल्स और एलपीजी सिलेंडर समेत इन नियमों में होंगे बदलाव

नई दिल्ली । साल 2022 का पहला महीना 31जनवरी को खत्म हो रहा है और कल से साल का दूसरा महीना शुरू होने वाला है। यानी कल से फरवरी का महीना शुरू हो रहा है ऐसे में बैंकिंग से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आप इन नए नियमों के बारे में जरूर जान लें। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक ध्यान दें! कल 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियम में बदलाव होने वाला है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक को वापस भी किया जा सकता है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है-हमारा सुझाव है कि आप सीटीएस क्लीयरिंग के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा का लाभ लें। बता दें कि यह बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए हैं। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो अब आपको पैसे ट्रांसफर करना महंगा पड़ने वाला है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, बैंक ने 1 फरवरी 2022 से आईएमपीएस ट्रांजेक्शन में एक नया स्लैब जोड़ा है, जो 2 लाख से 5 लाख रुपये का है। अगले महीने से 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच बैंक ब्रांच से आईएमपीएस के माध्यम से पैसे भेजने का शुल्क 20 रुपये प्लस GST लगेगा। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक भी अगले महीने से एक अहम नियम बदलने जा रहा है। पीएनबी के मुताबिक, 1 फरवरी से आपकी किसी किस्त या निवेश का डेबिट अकाउंट में पैसा न होने की वजह से फेल होता है तो इसके लिए 250 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतें तय होती है। इस बार 1 फरवरी को बजट पेश होना है ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एक फरवरी को सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ता है।

8 सालों में अदाणी टोटल गैस सीजीडी में करेगा 20 हजार करोड़ का निवेश

नईदिल्ली । सिटी गैस वितरण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) ने अगले आठ वर्षों में इस क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की तैयारी की है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ, एटीजीएल 9 मिलियन से अधिक घरों में खाना पकाने और पानी गर्म करने के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस प्रदान कर रहा है, साथ ही लगभग 2,000 सीएनजी स्टेशन स्थापित करके वाहनों के लिए इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट फ्यूल तथा इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को क्लीन फ्यूल उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। इन महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, एटीजीएल 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अतिरिक्त इन 14 अतिरिक्त जीए में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एटीजीएल की कुल प्रतिबद्धता को 20,000 करोड़ रुपये तक ले जाना भी शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा हाल ही में आयोजित एक सीजीडी बोली के 11वें राउंड में अपने सीजीडी नेटवर्क को 14 नए भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) तक बढ़ाने का लाइसेंस प्राप्त किया है।

भारत सबसे तेजी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक : कोविंद

देश को विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से 1.97 लाख करोड़ रुपए की लागत से 14 महत्वपूर्ण उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई

नईदिल्ली । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए सोमवार को कहा कि देश को विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से 1.97 लाख करोड़ रुपये की लागत से 14 महत्वपूर्ण उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गयी है जिससे 60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगें।

राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर केन्द्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए एक लाख 97 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण पीएलआई स्कीमें शुरू की हैं। ये स्कीमें न केवल भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगी।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा

उन्होंने देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता को मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे भारत के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। देश इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बने, इसके लिए सरकार ने सिनिकॉन और कंपाउंड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले एफएबी, चिप डिजाइन और इनसे जुड़े उद्यमों के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपये का पैकेज भी घोषित किया है। उन्होंने देश में पिछले कई महीनों से जीएसटी राजस्व संग्रह के एक लाख करोड़ रुपये के पार बने रहने का हवाला देते हुए कहा कि इस वित्त-वर्ष के पहले सात महीनों में 48 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आना, इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं।

भारत के निर्यात ने भी पिछले कई रिकार्ड तोड़े

निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकार्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान भारत का वस्तु निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर यानि 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जोकि 2020 की इसी अवधि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है। उन्होंने स्टार्टअप ईको-सिस्टम का जिक्र करते हुये कहा कि यह युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से देश में 56 अलग-अलग सेक्टरों में 60 हजार नए स्टार्ट-अप बने हैं। इन स्टार्ट-अप के जरिए छह लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न-स्टार्ट-अप अस्तित्व में आए जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है।

एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड

राष्ट्रपति ने भारत की समृद्धि में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुये कहा कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं और आत्म-निर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई को संकट से बचाने और जरूरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल मुक्त ऋण की व्यवस्था की। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना की सहायता से साढ़े 13 लाख एमएसएमई को जीवनदान दिया गया और डेढ़ करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए। जून 2021 में सरकार, तीन लाख करोड़ रुपए की इस गारंटी को बढ़ाकर साढ़े चार लाख करोड़ रुपए कर चुकी है।

शेयर बाजार में उछाल

सेंसेक्स 58 हजार अंक और निफ्टी 17300 अंक के पार

मुंबई । संसद के बजट सत्र के शुभारंभ के मौके पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले जबरदस्त तेजी के साथ बीएसई का सेंसेक्स 58 हजार अंक के पार और निफ्टी 17300 अंक के ऊपर निकल गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 645 अंकों की तेजी के साथ 57845.91 अंक पर खुला और देखते ही देखते यह 58 हजार अंक के उच्चतम स्तर 58069.13 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान शुरूआत में ही यह 57746.15 अंक के निचले स्तर तक उतरा भी। अभी यह 807.73 अंक अर्थात 1.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 58007 अंकों पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 200 अंकों की बढ़त के साथ 17301.05 अंक पर खुला। लिवाली के बल पर यह 17361.65 अंक के उच्चतम स्तर तक चढ़ा। इसी दौरान यह 17264.15 अंक के निचले स्तर तक उतरा। अभी यह

241.45 अंक अर्थात 1.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17343.40 अंक पर कारोबार कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज ही वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी और कल वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर निवेशक उत्साहित हैं और इसका असर बाजार पर आज से ही दिखने लगा है।

ड्रिलमेक एसपीए का तेलंगाना रिंग विनिर्माण का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का करार

नईदिल्ल । मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) समूह की सहायक कंपनी ड्रिलमेक एसपीए हैदराबाद तेलंगाना में अपना वैश्विक विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी।इस संबंध में करार पर ड्रिलमेक एसपीए के सीईओ सिमोन ट्रेविसानी और राज्य के उद्योग एवं औद्योगिक संवर्धन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव जयेश रंजन ने हस्ताक्षर किए।

ड्रिलमेक स्पा, तेल-ड्रिलिंग रिग निर्माण में एक वैश्विक कंपनी है। ड्रिलमेक ने तेलंगाना में तेल निकालने और सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रिलमेक इंटरनेशनल हब की स्थापना के लिए तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। वैश्विक हब की स्थापना के लिए आगामी सुविधा में 20 करोड़ डालर से अधिक का निवेश करने का प्रस्ताव है, जिसमें विनिर्माण, अनुसंधान और विकास और उत्कृष्टता केंद्र शामिल होंगे। लोगों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण। श्री ट्रेविसानी ने कहा, ''हम भारत में हाइड्रोजन ईंधन परियोजना में भविष्य के निवेश में रुचि रखते हैं। हैदराबाद विनिर्माण केंद्र रिग निर्माण और सहायक कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सुविधा अनुसंधान एवं विकास और उत्कृष्टता के प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना करती है। इटली, अमेरिका और बेलारूस में पहले से ही 3 विनिर्माण सुविधाएं हैं। विभिन्न देशों के कई प्रस्तावों पर विचार करने के बाद तेलंगाना का चुनाव किया गया है क्योंकि इसकी एक प्रगतिशील औद्योगिक नीति और निवेशक-अनुकूल है।ड्रिलमेक एसपीए तटवर्ती और अपतटीय अनुप्रयोगों के लिए ड्रिलिंग और वर्कओवर रिग के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के साथ-साथ ड्रिलिंग उपकरण के लिए स्पेयर पार्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला में एक वैश्विक नेता है। ड्रिलमेक को विश्वव्यापी विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा प्राप्त है। यह व्यापक इंजीनियरिंग विकास, समय पर डिलीवरी और प्रभावी बिक्री के बाद सेवा का प्रतिबिंब है। ड्रिलमेक ने करीब 600 ड्रिलिंग रिग उपलब्ध कराये हैं।

बाजार समीक्षा अक्टूबर-दिसंबर के दौरान 17 लाख टन चीनी का निर्यात

शकर का बकाया स्टॉक घटने के आसार

इंदौर। मौजूदा शकर सीजन 2021-22 के अंत में बकाया स्टॉक घटकर 65-70 लाख टन रहने के आसार है, जो कि गत सीजन के अंत में करीब 82 लाख टन शेष था। वर्ष 2016-17 के सीजन का अंतिम स्टॉक 34 लाख टन रहने के बाद यह 5 साल का सबसे न्यूनतम स्तर है, विगत 10 वर्ष में यह दूसरा सबसे कम स्टॉक होगा। दरअसल, एथेनॉल में इसका उपयोग बढ़ने के कारण स्टॉक में कमी संभावित है।

शकर के अंतिम स्टॉक में यह संभावित कमी चीनी मिलों के लिए वरदान मानी जा रही है, क्योंकि इसके चलते चीनी उद्योग को किसानों का बकाया भुगतान चुकाने में मदद मिलेगी। साथ ही अधिशेष चीनी के रखरखाव की समस्या से भी निजात मिलेगी। चीनी मिलों पर बिकवाली का दबाव कम रहेगा एवं इन्हें शकर की कीमतें सुनिश्चित करने में भी यह स्थिति मददगार होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू सीजन में शकर

उत्पादन 314 लाख टन अनुमानित है। वहीं इसमें से करीब 34 लाख टन चीनी को एथेनॉल की ओर मोड़ने के बाद खपत और निर्यात घटाकर शेष स्टॉक 65-70 लाख टन रहेगा। इंडियन शुगर मिल्स एसो.(इस्मा) के मुताबिक बंदरगाह की जानकारी के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में करीब 17 लाख टन चीनी भौतिक रूप से निर्यात हुई है। गत वर्ष इसी अवधि में 4.5 लाख टन निर्यात हुई थी। वहीं जनवरी 2022 में लगभग 7 लाख टन चीनी निर्यात के लिए पाइपलाइन में है।

सोया रिफाइंड में तेजी कायम सोयाबीन में प्लांटों की मांग कम

इंदौर। सोयाबीन रिफाइंड एवं सोयाबीन की कीमतों में सोमवार को तेजी-मंदी का विपरीत असर दिखाई दिया। भारतीय डीओसी के दाम वैश्विक कीमतों से 230-250 डॉलर प्रति टन ऊंचे होने से निर्यात घट रहा है। लिहाजा, सोयाबीन में तेल प्लांटों की मांग कम है। देश में सोयाबीन आवक 2.20 लाख व सरसों आवक 1.25 लाख बोरी की रही। जयपुर में तेल कंडीशन आधारित सरसों 150 रु बढ़कर 7850 रु थी। सोयाबीन प्लांट सौदों में धानुका 6315, रूचि 6275, अंबिका 6250, कृति 6260, रामा 6200, प्रकाश 6320, महाकाली 6250, प्रेस्टीज 6250, अवि 6225, लक्ष्मी 6250, अंबूजा 6100 रु क्विंटल के भाव थे। खाद्य तेल प्रति 10 किलो सोया रिफाइंड 1260-1265, साल्वेंट 1215-1220, मुंबई रिफाइंड 1260, मूंगफली तेल 1340-1360, मुंबई 1340, गुजरात 1300, पाम तेल मुंबई 1220, इंदौर 1290, कपास्या तेल 1240 रु के भाव बताए जा रहे थे।

कपास्या खली सामान्य - दाम प्रति 60 किलो इंदौर 2125, देवास-उज्जैन 2125-2130, खंडवा-बुरहानपुर 2100-2105, अकोला 3200 रु प्रति क्विंटल बताई जा रही थी।

एथनॉल आपूर्ति 302 करोड़ लीटर से अधिक अनुमानित

नई दिल्ली। वर्ष 2020-21 एथनॉल आपूर्ति वर्ष में पेट्रोल के साथ एथनॉल मिश्रण स्तर 8.1 फीसदी का अनुमान है। सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण लक्ष्य 20 प्रतिशत तय किया है। अनुमान है कि 2022 के दौरान 10 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इस वर्ष एथनॉल आपूर्ति 302 करोड़ लीटन से अधिक होगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने चीनी मिलों से जुड़े या डिस्टिलरीज को विभिन्न फीड स्टॉक जैसे बी-हाई और सी-हाई शीरा, गन्ना रस, चीनी सिरप, चीनी और एफसीआई के अधिशेष चावल, मक्के आदि सहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है।

गेहूं उत्पादन में कमी की आशंका, मक्का मजबूत

इंदौर। बुआई में कमी एवं मौसम की खराबी से कुछ क्षेत्रों में फसल खराब होने के समाचारों के चलते नए सीजन में गेहूं के उत्पादन में कमी की आशंका है। इसके चलते वर्तमान में बिकवाली कम होने से दाम मजबूत बने हुए है। मक्का की आपूर्ति जटिल होने से कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। सोमवार को मंडी में गेहूं चालू 2050-2150, मध्यम 2275-2450, बेस्ट 2500-2750, शरबती 3000-3250,डिलीवरी सौदो में इंदौर, देवास, पीथमपुर, 2150-2180, जलगांव अमलनेर, धुलिया 2200, नगर-औरंगाबाद 2280, हैदराबाद 2460, बैंगलुरु 2500 रु थे। मंडी में मक्का 1900-2050, डिलीवरी सौदो में इंदौर 2050, घाटाबिल्लोद 2020, आणंद-अहमदाबाद 2200, धुलिया 2150 रु थी।

चना घटकर 4800 रु, तुवर सुधरी

इंदौर। चने की बंपर पैदावार की उम्मीद के बीच नई आवक बढ़ने से पहले ही मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। सोमवार को दाम गिरकर 4800-4825 के रह गए। तुवर में सुधार था।

मंडी में डॉलर चना 2500 बोरी आवक के बीच 7000-8200, निर्यात में 42-44 काउंट 8300-8350, 58-60 काउंट 7300-7350, चना कांटा 4800-4825, विशाल 4600 -4625, डंकी चना 4000-4100, मसूर 7100-7125, उड़द 6350-6800 एवरेज 4500-6000, मूंग 6800-7000, एवरेज 5500-6300, तुवर लोकल 4500-5500, महाराष्ट 6300-6350 कर्नाटक 6450-6500 थी।

चना दाल में 100 रु घटे

दालें- चना दाल 5700-6300, तुवर दाल 8100-8700, नई 9000-9700, मसूर दाल 8300-8600, मूंग दाल 8100-8400, मोगर 8550-8850, उडद दाल 8000-8300, मोगर 9300-9800 रु। **चावल-** दयाल दास अजित कुमार छावनी बासमती (921) 9500-10000, तिबार 8000-8500, पोनिया 7000-7500, दुबार 6000-65000, मोगरा 3500-5500, सैला 6000-8500, कालीमूंछ डिनरकिंग 7500, राजभोग 6000, दूबराज 3500-4000, परमल 2500-2700 हंसा सैला 2450-2600 हंसा सफेद 2300-2450 पोहा 3300-3800 रु।

इस्पात उत्पादन 18 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2021 में 18 फीसदी बढ़कर 11.8 करोड़ टन पहुंच गया, जबकि विश्व के अग्रणी चीन में उत्पादन 3 फीसदी घटकर 103.28 करोड़ टन हो गया।

वैश्विक उद्योग संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दूसरे बड़े इस्पात उत्पादक भारत ने 2020 में 10.03 करोड़ टन इस्पात उत्पादन किया था वहीं चीन ने इसी अवधि में 106.47 करोड़ टन उत्पादन किया। वर्ल्डस्टील की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 195.05 करोड़ टन हुआ था, जो वर्ष 2020 के कुल उत्पादन 188.04 करोड़ टन की तुलना में 3.7 फीसदी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जापान ने 9.63 करोड़ टन उत्पादन किया, जबकि 2020 में 8.32 करोड़ टन इस्पात उत्पादन किया। अमेरिका का उत्पादन इस वर्ष 8.6 करोड़ टन रहा, जो इससे एक वर्ष पहले 7.27 करोड़ टन था। रूस का उत्पादन 7.6 करोड़ टन, दक्षिण कोरिया का 7.06 करोड़ टन, तुर्की का 4.04 करोड़ टन, जर्मनी का 4.01 करोड़ टन रहा।

अंचल की मंडी

नीमच: पोस्ता, रायडा की कीमतों में सुधार, कलौंजी, मैथी, चना, सोया, इसबगोल मंदे

नीमच (शंकर बंसल)। सोमवार को मंडी में पोस्ता व रायडा मजबूत थे, जबकि कलौंजी, मैथी, चना, अलसी, सोयाबीन, मक्का व इसबगोल के दाम मंदे रहे। भाव- गेहूं 1930-2300, जौं 2600-2731, मक्का 1850-2100, सोयाबीन 5500-6250, रायडा 5400-7050, अलसी 7550-8335, तारामीरा 4800-4900, मूंगफली 4000-5400, चना 4390-4550, डॉलर चना 4000-8110, मसूर 5500-6868, उड़द 3500-5900, मैथी 4700-6700, धनिया 6000-9000, अजवाइन 8500-11500, इसबगोल 11000-12450, कलौंजी 15500-17800, तिल्ली 8000-9600, असगंध 11000-31000, पोस्ता 105000-152700, लहसुन 600-7640, प्याज 300-2100 रु। **मंदसौर-** मंडी में कुल 37693 बोरी आवक हुई। भाव इस प्रकार थे- मक्का 1745-1961, उड़द 2500-5051, सोयाबीन 5700-6301, गेहूं 1950-2226, चना 3980-4580, मसूर 4000-6952, धनिया 5400-8220, लहसुन 400-3000, नई लहसुन 2250-7650, मैथी 5700-6440, अलसी 6000-8350, सरसों 5700-6900, तारामीरा 4500-4922, इसबगोल 8000-12140, प्याज 250-2100, कलौंजी 12350-17342, तुलसी बीज 8001-20700, डॉलर चना 3900-7601, तिल्ली 7000-7700, मटर 4500, असालिया 5065-6011 रु। **खंडवा-** कपास 166 वाहन, 1 बैलगाड़ी आवक के बीच भाव- कपास 5600-10200, सोयाबीन 4500-8700, गेहूं 1880-2100, तुवर 4800-5801, मक्का 1776-1850, चना 3500-4561, उड़द 2641-3200, मूंग 4281 रु। **बड़नगर-** मंडी में आवक 6108 बोरी हुई। भाव- गेहूं लोकवन 1850-2100, गेहूं पूर्णा 1870-2226, चना इटालियन 4000-4700, चना विशाल 3700-4770, चना डॉलर 5900-7701, मसूर 5901, बटला 3001-5800, सोयाबीन 3320-8751, लहसुन 512-1312 रु। **खेतिया-** कपास 270 वाहन, 9 बैलगाड़ी आया, जो 8550-10290 रु बिका। **महू-** सोयाबीन 4400-6280, चना 4392-4401, बिटकी 3999-5499, डॉलर चना 5699-6800, गेहूं 1865-2126, मक्का 1670-1958 रु। **धामनोद-** कपास 94 वाहन, 35 बैलगाड़ी आवक के बीच भाव इस प्रकार थे- कपास 4705-10000, गेहूं 1975-2040, मक्का 1700-1896, सोयाबीन 5800-6005, डॉलर चना 6575, मौसमी चना 4675 रु। **खरगोन-** कपास 346 वाहन, 95 बैलगाड़ी आवक के बीच भाव-कपास 6000-10700, गेहूं 1980-2167, मक्का 1705-1901, तुवर 5011-5800, सोयाबीन 5757-6161 रु। **धार-** मंडी में 4899 बोरी कृषि उपज की आवक हुई। भाव-सोयाबीन 3140-7705, गेहूं मालव शक्ति 1900-2300, लोकवन 1810-2224, डॉलर चना 4580-7845, चना 4344-4770, मसूर 00, मैथी 00, बटला 2200-5405, मक्का 1820-1894 रु। **निमरानी-** गेहूं 1065 बोरी आवक के बीच भाव 1985-2055 रु। **भीकनगांव-** कपास 101 वाहन, 138 बैलगाड़ी आवक के बीच भाव-कपास 6000-10510, गेहूं 1980-2040, सोयाबीन 5100-8000, मक्का 1790-1925, तुवर 5151-5601, चना 4149-4501 रु। **बुरहानपुर-** मंडी 1469 बोरी आवक के बीच भाव-गेहूं 1915-1990, मक्का 1821-1862, ज्वार 1683, तुवर 4902-5815, सोयाबीन 5151-5900 रुपए क्विंटल।

कपड़ा उद्योग क्षेत्र द्वारा कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की मांग

चेन्नई। कपड़ा उद्योग क्षेत्र ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में सभी प्रकार के कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है, ताकि कीमतों में अप्रत्याशित तेजी पर रोक लगाई जा सके और उन्होंने मंत्री के समक्ष तथाकथित जमाखोरी का मुद्दा भी विशेष रूप से उठाया।

कॉटन की एक खंडी की कीमत अब 80000 रु पहुंचचुकी है, जो 2020 में मात्र 37000 रुपए थी। कॉटन की एक खंडी 356 किलो के बराबर होती है। सामान्यतया प्रति खंडी 1000 रु दाम बढने पर प्रति किलो सूत में 4 रु बढ़ जाता है। घरेलू कच्चे कपास के दाम पिछले वर्ष जनवरी 2021 से इस साल अब तक करीब 69 फीसदी बढ़े है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इस दौरान 65 फीसदी की वृद्धि हुई है। कॉटन और सूत के दामों में उछाल और वायदा सौदो के अलावा कॉटन की तथाकथित जमाखोरी को लेकर उद्योग में बड़ी चिंता है। उद्योग समूह और तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बाजार में करीब 8 करोड़ गांठों (एक गांठ बराबर 170 किलो) की कमी है।उद्योग संगठनों ने सीतारमण से कमोडिटी एक्सचेंजों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साझेदारी के विनियमन में, बाजार में जगह नहीं पाने वाले कॉटन को बाहर लाने व सीसीआई को न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ी अधिक कीमत पर कपास की खरीद करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। सूत्र के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस बात से पूरीतरह अवगत नहीं था, कि सीसीआई ने अब तक कपास की कोई खरीद नहीं की है।

सोना और घटा, चांदी के भाव में आंशिक सुधार

इंदौर। सोमवार को सोना-चांदी में विपरीत रुख था। बजट में सोने पर आयात शुल्क घटने की संभावना से लेवाली नगण्य थी। इसके चलते सोने में मांमूली नरमी देखी गई, वहीं चांदी में आंशिक सुधार दर्ज हुआ। कॉमेक्स पर सोना ऊंचे में 1794.5, नीचे में 1785.7 डॉलर एवं चांदी ऊंचे में 2273, नीचे में 2223 सेंट प्रति औंस थी। **इंदौर सराफा-** में सोना केश में 49300-49400, आरटीजीएस 49250 रु प्रति 10 ग्राम एवं चांदी केश में 62550-62650, आरटीजीएस 62500 रु थी। चांदी सिक्का 750 रु नग था। **रतलाम सराफा-** आरटीजीएस सोना 49150 रु, चांदी 62400 रु थी। **उज्जैन सराफा-** सोना 49500 रु प्रति 10 ग्राम, चांदी 62950 रु प्रति किलो थी।

वैश्विक सराफा

विवरण	सोना	चांदी
ऊंचे में	1794.50	22.73
नीचे में	1785.70	22.23
रनिंग में	1790-70	22.60

चीनी कोटा 20 लाख टन, तरबूज मगज मंदा

इंदौर। सरकार ने फरवरी 2022 के लिए मिलों को 20 लाख टन बिक्री कोटा जारी किया है, जो जनवरी के 21.50 लाख टन से कम है, जबकि गत वर्ष फरवरी के कोटे 17 लाख टन से ज्यादा है। तरबूज मगज में मंदी के चलते दाम गिरकर 190-210 रु किलो रह गए, जो एक माह पूर्व 250-260 रु थे। कालीमिर्च नए सिरे से 2 रु किलो मंदी रही। चने में मंदी से बेसन मंदा रहा।

थोक बाजार में भाव शकर 3480-3490, सुपर 3510-3520, एम 3625-3650, गुड़ भैली 2850-2900, कटोरा 3100-3200, लड्डू 3250-3350, बरफी 4000, कालीमिर्च कालामोती 521,दीपक 535 गणेश 551, मटरदाना 571, जीरा पंजा 216 खुशबू 218, सुपर 220-228, हल्दी सांगली 174-175, निजामाबाद 125-140, नारियल प्रति बोरी 120 भर्ती 1550-1600, 160 भर्ती 1500-1550, 200 भर्ती 1600-1650, 250 भर्ती 1750-1800, खोपरा गोला 208-230, खोपराबूरा 15 किलो 2400-4150, साबूदाना 4250-4600, वरलक्ष्मी 4950, ग्लास 5450, वरलक्ष्मी 1 किलो पैक 5650, सौंफ 150-205, हल्की 105-115, लौंग 670-740, दालचीनी 265-275, जायफल 750-800, जावत्री 1900-2000, बड़ी इलायची 751-800, तरबूज मगज 190-

210, चारोली 1050-1200, इलायची एक्स्ट्रा बोल्ड 1800-1850, बोल्ड 1650-1700 मध्यम 1550-1600, मिनी 1400-1500, पानपट्टी 1300-1400, पोस्ता 1200-1500, काजू (240) 770-790, (320) 690-705, डब्ल्यू वन (300) 670-680, एस एस डब्ल्यू 630-650, जेएच 620-630, टुकड़ी 600-650, बादाम इनडिपेंटेड 540-550, अमेरिकी 560-580, आस्ट्रेलियन 585-590, टांच 480, किशमिश 375-550, इंडियन 210-240, मखाना 675-900, पिस्ता 1275-1375, नमकीन 850-900 रु। **आटा-मैदा** (50 किलो) आटा 1225-1230, मैदा 1250-1260, रवा 1280-1285, बेसन 3150-3175 रु।

दर्शकों के बीच होगा भारत-वेस्टइंडीज मुकाबला:बंगाल सरकार ने 75फीसदी दर्शकों की इजाजत दी, कोलकाता में 50 हजार लोग देख सकेंगे टी-20 मैच

कोलकाता। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में 16 फरवरी से खेले जाने वाली टी-20 सीरीज के लिए बंगाल सरकार ने स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री की इजाजत दे दी है। 3 टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 16 फरवरी को खेला जाना है। बाकी के दोनों मैच भी यहीं पर होने हैं। बंगाल सरकार ने खेलों को लेकर जारी नोटिफिकेशन में 75 फीसदी दर्शकों की स्टेडियम में प्रवेश की इजाजत दी है। ऐसे में ईडन गार्डन्स में 50 हजार दर्शक मैच का मजा ले सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से खेलों को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी इनडोर और आउट डोर स्पोर्ट्स में 75 प्रतिशत दर्शकों की अनुमति होगी। ये तादाद स्टेडियम की क्षमता के अनुसार होगा।

CAB ने किया फैसले का स्वागत

इससे पहले पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के साथ टी-20 सीरीज के तीसरे मैच के लिए बंगाल सरकार ने 70 प्रतिशत दर्शकों को एंट्री के लिए मंजूरी दी थी। बंगाल सरकार की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए दर्शकों की एंट्री देने पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने बंगाल सरकार को इसके लिए धन्यवाद कहा।

कोरोना के चलते बदला गया शेड्यूल

वेस्टइंडीज के भारत दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी और टी-20 सीरीज के साथ खत्म होगी। पहले 3 टी-20 मैचों की सीरीज और 3 वनडे मैचों की सीरीज के सभी मैच अलग-अलग शहरों में खेले जाने थे, यानी 6 शहरों में मैच होने थे, लेकिन कोरोना के चलते वेस्टइंडीज के दौरे को 2 शहरों तक सीमित कर दिया गया। वनडे सीरीज के मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6, 9 और 11 फरवरी को खेले जाएंगे, जबकि टी-20 सीरीज के मैच 16, 18 और 20 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होंगे।

रणजी सीरीज के लिए शेड्यूल जारी: पहला चरण 16 से 5 मार्च तक; 8 शहरों में खेले जा सकता हैं लीग के मैच

नई ड्डिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी की लीग स्टेज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि, अभी जगह फाइनल नहीं की गई है। रणजी ट्रॉफी की लीग स्टेज 16 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होगी।

8 शहरों में खेले जा सकता हैं लीग के मैच

रणजी ट्रॉफी में 38 टीम हिस्सा लेंगी और इसके मैच 8 शहरों में खेले जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक रणजी मैच अहमदाबाद, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, कटक, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और राजकोट में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले रणजी ट्रॉफी 13 जनवरी से शुरू होनी थी। इसके लिए 6 शहरों का चयन किया गया था। जिनमें मुंबई, बेंगलुरू, अहमदाबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई शामिल थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इसे स्थगित करने का फैसला किया गया था। बाद में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने फरवरी और मार्च के बीच पहले चरण आयोजित कराने की घोषणा की थी।

टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है

टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। प्लेट ग्रुप को छोड़कर सभी ग्रुप्स में 4 टीमें होंगी। प्लेट ग्रुप में 6 टीमें होंगी। मार्च 2020 में रणजी ट्रॉफी फाइनल के बाद से भारत में लाल गेंद प्रारूप से राष्ट्रीय स्तर का कोई भी घरेलू मुकाबला नहीं खेला गया है।

टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी फिट: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले निशांत संधु की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव

दुबई। अंडर-19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले भारतीय खेमे से अच्छी खबर आई है। भारतीय खिलाड़ी निशांत संधु की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। भारत को बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल मैच खेलना है। निशांत संधु लीग मैच के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान यश धुल सहित 6 खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इसके बाद दो लीग मैच में निशांत संधु ने टीम की कप्तानी की। फिट होने के बाद कप्तान यश धुल सहित सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर वापसी कर ली थी। धुल ने क्वार्टर फाइनल में टीम की कप्तानी भी की थी।

आखिरी लीग मैच के बाद संधु संक्रमित

युगांडा के खिलाफ भारतीय टीम के अंतिम लीग मैच के बाद निशांत संधु की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद वह क्वारैंटाइन हो गए थे। भारत ने अपने तीनों लीग में मैच जीतकर अपने ग्रुप में टॉप पर था। भारत ने अपने आखिरी मैच में युगांडा को 326 रन से हराया था। उससे पहले साउथ अफ्रीका और आयरलैंड को हराया। अब सेमीफाइनल मैच के लिए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगे।

टीम इंडिया का कप्तान नहीं बन पाने पर हरभजन का छलका दर्द, बीसीसीआई पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पिछले साल 24 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब वह कई मामलों पर चुप्पी तोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने टीम में शामिल नहीं किए जाने को लेकर अपनी बात रखी थी। अब भज्जी ने टीम इंडिया का कप्तान नहीं बन पाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर भी अपना दुख जाहिर किया है।

'मैं कप्तान बनने के लायक था'

हरभजन ने दिए इंटरव्यू में करियर, विवाद और कप्तानी से जुड़े सवालों पर जवाब दिया। कप्तानी को लेकर सवाल पूछे जाने पर भज्जी ने कहा- ऐसा नहीं है कि मैं कप्तान बनने लायक नहीं था या मुझे कप्तानी नहीं आती थी। मेरे जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो बीसीसीआई में ऊंचे पद पर हो। कोई ऐसा नहीं था जो मेरे कप्तान बनने को लेकर बीसीसीआई से बात कर सके या मेरा समर्थन कर सके। अगर ऐसा कोई होता, तो शायद मैं भी टीम इंडिया का कप्तान होता।

'बीसीसीआई में पैरवी करने वाला कोई नहीं था'

भज्जी ने कहा- यदि आप बोर्ड में किसी दमदार सदस्य के पसंदीदा नहीं हैं, तो आपको ऐसा सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन हमें अब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे कप्तानी मिलती तो मैं भी अपना 100 फीसदी देता और टीम को आगे बढ़ने में मदद करता। मैंने एक खिलाड़ी के तौर पर भी हमेशा यही किया है।

'धोनी से कोई शिकायत नहीं है'-पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर भज्जी ने कहा- मुझे धोनी से कोई शिकायत नहीं है। हम कई सालों से एक अच्छे दोस्त हैं। मुझे उस समय के बीसीसीआई सरकार से शिकायत है। मैं बोर्ड को सरकार कह रहा हूं। उस समय के चयनकर्ताओं ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं किया। इससे टीम एकजुट नहीं हो सकी।

'2011 विश्व कप के बाद चैंपियन टीम साथ नहीं खेली'

भज्जी ने कहा- 2012 के बाद कई चीजें और बेहतर हो सकती थीं। मेरे अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और गौतम गंभीर भारतीय टीम के लिए खेलकर संन्यास ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैदान के बाहर ही हमें संन्यास लेना पड़ा। हम सभी उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। यह समझ से परे ही है कि 2011 विश्व कप के बाद चैंपियन टीम फिर कभी एक साथ नहीं खेली।

कुंबले के साथ कोई विवाद नहीं

हरभजन से यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को टीम में आपको तरजीह दिए जाने के बाद विवाद हुआ था? इसके जवाब में भज्जी ने कहा- मेरे मन में कुंबले के लिए बहुत सम्मान है। टीम इंडिया में उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं हुआ। मेरे लिए उनके साथ खेल पाना सौभाग्य की बात है। हां, कई मौकों पर मुझे उनके ऊपर प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई, लेकिन मैंने इस मसले पर कुंबले को परेशान नहीं देखा।

भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार, यह अवॉर्ड पाने वाले दूसरे हॉकी खिलाड़ी बने

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरूष हॉकी टीम का हिस्सा रहे पीआर श्रीजेश ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भारतीय गोलकीपर ने प्रतिष्ठित द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवॉर्ड अपने नाम किया। श्रीजेश यह पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 2019 में यह पुरस्कार जीता था। श्रीजेश ने दुनियाभर के 24 खिलाड़ियों को पछाड़ा। उन्हें 127,647 वोट मिले जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले स्पेन के स्पोर्ट क्लाइंबिंग खिलाड़ी अल्बर्ट गिनेस लोपेज़ को 67,428 वोट मिले। एफआईएच के 2021 के साल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए तीन बार के ओलंपियन श्रीजेश ने 240 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पिछले 12 महीने उनके लिए शानदार रहे और उन्होंने अपना

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टीम को टोक्यो खेलों में एतिहासिक कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। श्रीजेश ने पुरस्कार जीतने के बाद कहा, 'मैं यह पुरस्कार जीतकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले, मुझे इस पुरस्कार के लिए नामांकित करने के लिए एफआईएच का बहुत-बहुत धन्यवाद, और दूसरा दुनिया भर के सभी भारतीय हॉकी प्रेमियों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे वोट दिया। नामांकित होकर मैंने अपना काम किया, लेकिन का काम बाकी प्रशंसकों और हॉकी प्रेमियों ने किया। इसलिए, यह पुरस्कार उन्हें जाता है, और मुझे लगता है कि वे मुझसे अधिक इस पुरस्कार के पात्र हैं। यह भारतीय हॉकी के लिए भी एक बड़ा क्षण है क्योंकि हॉकी समुदाय में सभी ने, दुनिया भर के सभी हॉकी महासंघों ने मुझे वोट दिया है, इसलिए हॉकी परिवार से उस समर्थन को देखकर बहुत अच्छा लगा।'

द वर्ल्ड गेम्स डॉट ओआरजी द्वारा आयोजित आनलाइन मतदान प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चली। इस पुरस्कार के लिए दुनियाभर से कुल 24 खिलाड़ियों को नामित किया गया था। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्व खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय विश्व खेल संघ द्वारा हर चार साल में आयोजित एक बहु-खेल आयोजन है। यह कार्यक्रम 11 दिनों तक चलता है जिसमें 30 से अधिक खेलों को शामिल किया जाता है।

भारत ने अपने डेब्यू मैच में चीन को 7-1 से दी करारी शिकस्त

नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में जोरदार आगाज किया है। सविता पुनिया की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अपने पदार्पण मैच में चीन को करारी शिकस्त दी। मस्कट के सुल्तान क़ाबूस काम्प्लेक्स में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने एकतरफा मुकाबले में चीन को 7-1 से पटखनी दी।

भारतीय टीम ने आखिरी के 12 मिनट में ताबड़तोड़ पांच गोल दागे। भारत की तरफ से पहला गोल नवनीत कौर ने पांचवें मिनट में किया। इसके बाद 12वें मिनट में नेहा ने दूसरा गोल दागकर टीम को पहले क्वार्टर में 2-0 की मजबूत बढ़त दिलाई। इसके बाद वंदना कटारिया (40वें), सुशीला चानू (47वें और 52वें), शर्मीला देवी (48वें) और गुरजीत कौर (50वें) मिनट में गोल दागा। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले क्वार्टर में दो, तीसरे क्वार्टर में एक गोल और आखिरी क्वार्टर में एक के बाद एक चार गोल दागे। शर्मीला देवी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ़ दी मैच चुना गया।

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगे हार्दिक:बोले- टी-20 वर्ल्ड कप जीतना है टारगेट

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर चल रहे हार्दिक पंड्या ने खुलासा किया कि वह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगे। वह IPL 2022 से फिर से क्रिकेट में वापसी करेंगे। हार्दिक को अहमदाबाद टीम ने अपना कप्तान बनाया है। इसके अलावा टीम ने राशिद खान और शुभमन गिल को भी अपने साथ जोड़ा है। IPL में इस बार 8 की जगह 10 टीमें उतर रही हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में इस साल टी-20 वर्ल्ड कप अक्टूबर- नवंबर में होना है। भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक ही ग्रुप में रखा गया है। पंड्या 2021 में फिनटेस के चलते गेंदबाजी नहीं कर सके थे। वह बतौर बल्लेबाज भी विफल रहे। हार्दिक ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मेरी तैयारी टी-20 वर्ल्ड कप समय पूरी तरह से तैयार रहने को लेकर चल रही है। सारी ट्रेनिंग और प्लानिंग इसी को ध्यान में रखकर हो रही है। मैं देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। IPL 2022 मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मेरी पूरी तैयारी भारतीय टीम और वर्ल्ड कप के लिए है।'हार्दिक पंड्या पहली बार IPLमें मुंबई इंडियंस के अलावा किसी और टीम के साथ खेलेंगे। उन्होंने IPLमें करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस से 2015 में की है।

लखनऊ सुपर जाएंट्स ने जारी किया लोगो

नई दिल्ली। लखनऊ सुपर जाएंट्स ने टीम का लोगो जारी कर दिया है। यह लोगो एक चिड़िया के आकार का है और तिरंगे के रंग का है। लोगो के बीच में बल्ला बना हुआ है।

बल्ला नीले रंग का है और उसके बीचो बीच लाल रंग की एक गेंद बनी हुई है। टीम का नाम भी नीले रंग में लिखा गया है। लखनऊ की टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर लोगो का खुलासा किया है। इसका एलान करते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स ने कैप्शन में लिखा- महानता की ओर बढ़ते हुए। लखनऊ सुपर जाएंट्स अपने पंख फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। महानता की तैयारी करो!

क्या है लखनऊ के लोगो का मतलब ?

लखनऊ सुपर जाएंट्स ने अपने लोगो का मतलब भी बताया है। फ्रेंचाइजी की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया 'लखनऊ सुपर जायंट्स, भारत की नई आईपीएल टीम का लोगो भारत की पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। पौराणिक पक्षी गरुड़ - जो रक्षक है और तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम है। उससे प्रेरित होकर हमने पंखों वाला लोगो बनाया है। गरुड़ भारतीय संस्कृति में सर्वव्यापी है। वहीं लोगो के तीन रंग के पंख पूरे देश में लखनऊ की टीम की अपील को दर्शाते हैं। चिड़िया का शरीर नीले रंग के बैट से दर्शाया गया है, जो कि क्रिकेट के खेल का रंग है। वहीं नारंगी सीम वाली लाल रंग की गेंद विजय तिलक की तरह है। यह लोगो कुल मिलाकर एक सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, जो लगातार आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने की प्रेरणा देती है। लखनऊ सुपर जायंट्स हर भारतीय की टीम है। यह एक ऐसी टीम है जो देश को एकजुट करती है।'

विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद तोड़ी चुप्पी, पहली बार पूरे मामले पर रखा अपना पक्ष

मुंबई। विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। पूर्व भारतीय कप्तान ने अपने फैसले पर चुप्पी तोड़ते हुए पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। विराट का कहना है कि उन्हें टीम का नेतृत्व करने के लिए कप्तान रहने की जरुरत नहीं है।

विराट ने फायराइड चैट से बातचीत के दौरान कहा, 'महेंद्र सिंह धोनी भी भारत की कप्तानी छोड़ने के वक्त टीम का हिस्सा थे। कप्तानी से हटने के बाद भी वो टीम के लीडर थे। धोनी ऐसे शख्स थे जिनसे हमने काफी सुझाव लिए। जब मैं भारत का कप्तान बना तो मेरा लक्ष्य टीम का कल्चर चेंज करने का था क्योंकि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसमें इतने कुशल खिलाड़ी हों। विराट अब बतौर बल्लेबाज भारतीय टीम की तरफ से खेलेंगे। उन्होंने इसपर कहा, ÷मुझे लगता है कि आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या आप उसे हासिल कर पाए हैं या नहीं? हर चीज की एक समय सीमा होती है और आपको उसके बारे में मालूम रहना चाहिए। एक बल्लेबाज के रूप में आप टीम को ज्यादा दे सकते हैं, इसलिए उसमें गर्व महसूस करें।' उन्होंने आगे कहा, 'आगे बढ़ना भी लीडरशिप का ही हिस्सा है। मुझे लगता है कि किसी को हर भूमिका और जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना

चाहिए। मैंने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में खेला और फिर कप्तान बना लेकिन मेरी सोच हमेशा एक ही रही। मैंने हमेशा एक कप्तान की तरह सोचा है। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की जिसमें टीम इंडिया को 40 में जीत मिली जो किसी भी भारतीय कप्तान की तुलना में अधिक है।

दक्षिण अफ्रीका के 'बेबी डिविलियर्स' ने 73 के औसत से 368 रन बनाए, अब आईपीएल में करना चाहते हैं कमाल

मुंबई। अंडर-19 विश्वकप 2022 में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर डेवाल्ड ब्रेविस सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी हैं। उनको बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से ख्याति मिल रही है। ब्रेविस ने इस टूर्नामेंट में पूर्व अफ्रीकी दिग्गज डिविलियर्स के अंदाज में बल्लेबाजी भी की है। उन्होंने अंडर-19 विश्वकप के पांच मैचों में 73 के औसत से 368 रन अपने नाम किए हैं। वे अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं।

ब्रेविस पूरी तरह से बेखौफ होकर शॉट लगाते हैं और उनके खेलने का अंदाज बहुत हद तक डिविलियर्स से मिलता है। इसी वजह से उन्हें बेबी एबी डिविलियर्स कहा जा रहा है। अंडर-19 विश्वकप में ब्रेविस 11 छक्के और 34 चौके भी लगा चुके हैं। उनका सपना है कि अंडर-19 टीम के बाद वो दक्षिण अफ्रीका की मुख्य टीम के लिए भी खेलें और इसी अंदाज में रन बनाएं। वो आईपीएल में भी विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा बनना चाहते हैं।

डिविलियर्स की तरह ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ब्रेविस

ब्रेविस भी एबी डिविलियर्स की तरह ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। वो लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बल्ले के साथ भी विस्फोटक अंदाज में खेलने की क्षमता रखते हैं। डिविलियर्स भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। हालांकि, उन्होंने गेंद के साथ ज्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपिंग और गेंदबाजी दोनों काम किए हैं। ब्रेविस क्रिकेट के तीनों फार्मेट खेलना चाहते हैं।

टूर्नामेंट में सातवें स्थान के लिए खेलेगी अफ्रीकी टीम- दक्षिण अफ्रीका की टीम अंडर-19 विश्व कप से बाहर हो चुकी है। क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हराया था। इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। पहले ही मैच में भारत ने अफ्रीकी टीम को 45 रन से हराया था। इसके बाद युगांडा और आयरलैंड के खिलाफ यह टीम जीती, लेकिन इंग्लैंड से हार गई। अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी दक्षिण अफ्रीका को 65 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अब यह टीम सातवें स्थान के लिए तीन फरवरी को मैच खेलेगी।

टिम ब्रेसनन ने किया संन्यास का ऐलान:इंग्लैंड के लिए जीत चुके हैं टी-20 वर्ल्ड कप

वारविकशायर। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम ब्रेसनन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काउंटी क्रिकेट क्लब वारविकशायर ने इस बात की पुष्टि की है। 36 वर्षीय दाएं हाथ के खिलाड़ी ने 20 साल तक प्रोफेशल क्रिकेट खेला।

मेरे लिए सबसे कठिन फैसला

ब्रेसनन ने वारविकशायर काउंटी को दिए एक बयान में कहा- यह अविश्वसनीय रूप से मेरे लिए कठिन फैसला रहा, लेकिन सर्दियों में ट्रेनिंग के लिए लौटने के बाद मुझे लगा कि अब क्रिकेट को अलविदा कहने का सही समय है। मैंने अपने 21वें पेशेवर साल की तैयारी के लिए पूरे ऑफ सीजन में कड़ी मेहनत जारी रखी। लेकिन गहराई से मुझे लगता है मैं उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, जो मैंने खुद के लिए और साथी खिलाड़ियों के लिए तय किए हैं।

उन्होंने आगे कहा- खेल के लिए जो भूख और उत्साह मेरा अंदर था, मुझे लगता है कि वो कभी नहीं छूटेगा। मेरा दिल तो कह रहा है कि 2022 का सीजन में खेल सकता हूं, लेकिन शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा अपने करियर को बड़े गर्व के साथ देखूंगा और वारविकशर और देश का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है।

इंग्लैंड के लिए जीता टी-20 वर्ल्ड कप

साल 2010 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी-20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। उस समय टिम ब्रेसनन भी ENG की टीम का हिस्सा था। 2010-11 में इंग्लैंड ने जब ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3-1 से हराकर एशेज सीरीज जीती थी, तब ब्रेसनन भी इंग्लैंड टीम का हिस्सा था। उस सीरीज के दो मैचों में उन्होंने 19.55 की औसत के साथ कुल 11 विकेट चटकाए थे।

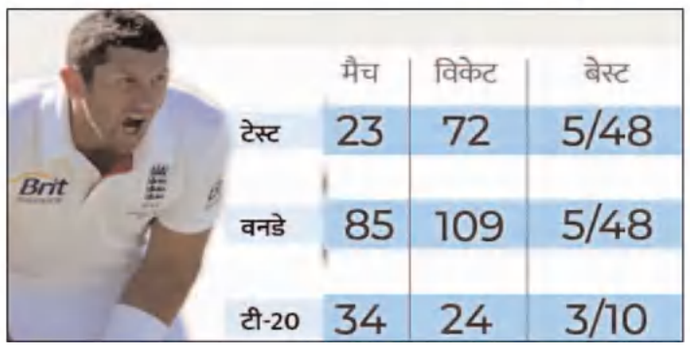

	मैच	विकेट	बेस्ट
टेस्ट	23	72	5/48
वनडे	85	109	5/48
टी-20	34	24	3/10

कोहली को किया चार बार आउट

ब्रेसनन ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को वनडे में 3 और टी-20 इंटरनेशनल में 1 बार आउट किया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैचों में 72, 85 वनडे में 109 और 34 टी-20I में कुल 24 विकेट चटकाए। 2015 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम पर 575 विकेट और 7 शतक भी दर्ज है।

केंद्रीय बजट में कोई राजनीति नहीं : पीएम मोदी

राजेश अलख

नई दिल्ली, 01 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी माहौल में भी किसी भी दबाव से झुकने से इनकार कर दिया है क्योंकि मंगलवार को घोषित केंद्रीय बजट में किसी भी लोकलुभावन वादे का कोई उल्लेख नहीं है।

इस महीने पांच राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन एक बजट अवलोकन आपको आश्चर्यचकित कर देगा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया है और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए लोकलुभावन होने का कोई संकेत नहीं है।

वित्त मंत्री का फोकस विकास पर रहा है और फिन टेक, स्टार्ट अप, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल रुपया, ड्रोन, सौर ऊर्जा, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए युग के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से और ड्रोन-एस-ए-सर्विस (डीआरएएएस) के लिए 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा के लिए बजट में घोषित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों में चुनिंदा आईटीआई में स्किलिंग के लिए जरूरी कोर्स शुरू किए जाएंगे।

शिक्षा वितरण के लिए पीएम ईविद्या के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना देश भर के छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाएगी। इसे विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय एक नेटवर्क हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब बिल्डिंग अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता होगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब-स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी।

गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, एक 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा। इसमें एक्सिलेंस के 23 टेली-मेंटल स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निमहंस नोडल केंद्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (आईआईआईटीबी) प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा।

हाल के वर्षों में, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में उपभोक्ता-हितैषी तरीके से पहुंचे। इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

नागरिकों को उनकी विदेश यात्रा में सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और अंतर-संचालन मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को 'सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा' के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी इको-सिस्टम में दक्षता में सुधार होगा।

भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग एक मजबूत अनिवार्यता है। रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्यों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिड्यूल 8 की किसी भी भाषा में भूमि अभिलेखों की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

बजट की घोषणा की गई है कि सामान्य रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5जी तकनीक, विकास को सक्षम कर सकती है और नौकरी के अवसर प्रदान कर सकती है। निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के रोलआउट की सुविधा के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियलसिस्टम और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स, ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम में देश के बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता करने और आधुनिकीकरण करने की अपार संभावनाएं हैं। वे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और भारतीय उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

सहायक नीतियां, हल्के-फुल्के नियम, घरेलू क्षमता निर्माण के लिए सुविधाजनक कार्रवाई और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना सरकार के ऑप्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। इन सूर्योदय के अवसरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए, शिक्षा, उद्योग और सार्वजनिक संस्थानों के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा, बजट के एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में सरकारी योगदान प्रदान किया जाएगा।

2030 तक 280 गीगावॉट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण की सुविधा के लिए, पॉलीसिलिकॉन से सौर पीवी मॉड्यूल तक पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ हाई एफिशियेंसी मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, बनाया जायेगा।

वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया, जिससे सबसे बड़े स्टार्ट-अप और ग्रोथ इकोसिस्टम में से एक की सुविधा हुई। इस निवेश को बढ़ाने के लिए नियामक और अन्य बाधाओं की समग्र जांच की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि जांच करने और उचित उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा एक अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को भी बढ़ावा देगी। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से जारी किए जाने वाले ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए, डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है।

देशभर के छात्रों के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी : वित्त मंत्री

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। भारत सरकार ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी।

दरअसल बीते 2 वर्षों के दौरान कोरोना महामारी के कारण छात्रों एवं शैक्षणिक जगत को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। जहां एक और स्कूल कॉलेज बंद रहे वहीं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को सुऑढ़ता प्रदान करने के लिए बाकायदा एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने का बजट प्रावधान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही। उन्होंने बताया यह डिजिटल विश्वविद्यालय देशभर के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक बहुभाषी विश्वविद्यालय होगा जिसका लाभ भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र ले सकेंगे।

वित्त मंत्री के मुताबिक भारत का यह डिजिटल विश्वविद्यालय उच्चतम एवं बेहतरीन टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल विश्वविद्यालय से देश के कई विख्यात विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा।

अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके देश के नामी विश्वविद्यालय इस डिजिटल विश्वविद्यालय की मदद करेंगे। देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों की सहायता से यहां पाठ्यक्रमों को बनाया और लागू किया जाएगा। साथ ही फेकल्टी और छात्रों को भी इस अनुभव का लाभ प्राप्त होगा।

गौरतलब है कि स्वयं शिक्षा मंत्रालय बीते 2 वर्ष के दौरान शिक्षा के डिजिटल माध्यमों को सशक्त बनाने का प्रयास करता रहा है। छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल 'दीक्षा' को प्रतिदिन 5 करोड़ से अधिक हिट मिल रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए 'नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर' को मजबूत कर रहा। इसके साथ ही सभी ग्रेड के लिए विशेष क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक, एक डिजिटल ख्लेटफॉर्म तैयार की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई यह डिजिटल पाठ्य सामग्री दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक दीक्षा में 402 करोड़ से अधिक शिक्षण सत्र, 4,844 करोड़ से अधिक सीखने के मिनट और 5 करोड़ से अधिक औसत दैनिक पृष्ठ हिट के साथ 2,730 करोड़ से अधिक पृष्ठ हिट हैं।

मंत्रालय का कहना है कि आज की तारीख में दीक्षा पर कुल 2,27,704 ई-कंटेंट लाइव हैं। वहीं वर्ष 2022 -23 के बजट में ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक मजबूती देने के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जहां डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है वहीं स्कूली छात्रों के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं जिनमें डीटीएच आधारित टीवी चैनल्स की संख्या बढ़ाना शामिल है।

केंद्रीय बजट सकारात्मक, स्वागतयोग्य : सीएम नीतीश

पटना, 01 फरवरी (का.सं.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागतयोग्य और सकारात्मक बताया है। उन्होंने इसे संतुलित बजट बताते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई भी दी है।

नीतीश ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, पिछले दो वर्षों में देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय हैं। संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को मैं बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण के लिहाज से भी स्वागतयोग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कोरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि बजट में धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। जदयू नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए आवास बनाने की घोषणा हुई है, यह स्वागतयोग्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों को केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी, जिससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी।

अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट, केवल दो बार आया 'गरीब' शब्द : पी. चिदंबरम

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को पेश किया गया आम बजट अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट बताया। उन्होंने कहा कि पूरे बजट भाषण के दौरान केवल दो बार ही 'गरीब' शब्द बोला गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में करों को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल से इस परंपरा को जारी रखा है, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे कोविड-19 के दौरान आम आदमी पर अधिक करों का बोझ न डालें।

हालांकि विपक्ष बजट आने के बाद से लगातार हमलावर है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, 'आज का बजट भाषण किसी वित्त मंत्री द्वारा पढ़ा गया अब तक का सबसे पूंजीवादी भाषण था। 'गरीब' शब्द पैरा 6 में केवल दो बार आता है और हम वित्त मंत्री को यह याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग भी हैं। लोग इस पूंजीवादी बजट को खारिज कर देंगे।'

पी चिदंबरम ने कहा, 'मैं चकित, स्तब्ध था कि वित्त मंत्री अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार कर रही थीं। सरकार को लगता है कि वर्तमान पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और जनता को 'अमृत काल' के उदय होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है। यह भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जाना है।'

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वर्चुअल डिजिटल ऐसेट्स पर टैक्स को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, 'यह (बजट 2022) जाहिर तौर पर देश के बहुत अमीर लोगों के इशारे पर है। आरबीआई के बजाय, वित्त मंत्री ने वस्तुत: घोषणा की है कि क्रिप्टोकरेंसी आज से कानूनी है। अब यह सब भारत के 99.99 प्रतिशत लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है।'

संसद में बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्वतंत्रता के 100 वर्षों में भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'अमृत काल' के दौरान कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करके इस दृष्टि को प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट 'अमृत काल' पर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नींव रखना और एक खाका देना चाहता है।

आम बजट दूरदर्शी : अमित शाह

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने इसे दूरदर्शी बजट बताया है।

अमित शाह ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को दूरदर्शी करार दिया और दावा किया यह यह भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला साबित होगा।

बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा।

शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का बजट कोरोना के बाद वैश्विक आर्थिक जगत में उत्पन्न हुए अवसरों का दोहन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा, बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना,

'भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला'

कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत राजकोषीय घाटे को चार प्रतिशत से नीचे लाने में सफल होगा।

उन्होंने कहा, मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा।

निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए खोली 'तिजोरी', की अहम घोषणाएं

नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया, जिस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये खजाना खोलते हुए 39.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से राजमार्गों से लेकर सस्ते मकानों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।

वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है।

लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने पूंजी व्यय 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया। साथ ही सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये रियायती दर की समयसीमा बढ़ाने के साथ डिजिटल मुद्रा शुरू करने तथा क्रिप्टो संपत्तियों पर कर लगाने के भी प्रस्ताव किये हैं।

पिछले साल की तरह इस बार भी बजट में बुनियादी ढांचा खर्च पर अच्छा-खासा जोर है। इसमें 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, नदियों को जोड़ने की योजना तथा नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण शामिल है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तेज वृद्धि के लिये आधार रखने का संकल्प जताते हुए कहा, अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना और पुनरुद्धार हमारे देश की मजबूती को बताता है।

उन्होंने कहा, बजट में राजकोषीय मजबूती की जगह आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दी गयी है। बजट वृद्धि के लिये निरंतर गति प्रदान करता रहेगा।

बजट में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है जबकि पूर्व में इसके 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी थी। लेकिन अगले वित्त वर्ष 2022-23 में इसके कम होकर 6.4 प्रतिशत तथा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत पर आने का अनुमान रखा गया है।

आर्थिक वृद्धि दर के बारे में इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 9.2

प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5 प्रतिशत रहेगी। वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

सीतारमण ने कहा, बजट का रुख विकास के सात इंजन...सड़क, रेलवे, हवाईअड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे... पर आधारित है। ये बुनियादी ढांचे के प्रमुख क्षेत्र हैं।

उन्होंने कहा, ऊर्जा बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, जल एवं जल निकासी क्षेत्र तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ सातों इंजन अर्थव्यवस्था को समान गति से आगे बढ़ाएंगे।

बजट प्रस्तावों में परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्रों (गति शक्ति), बैंकिंग और वित्तीय प्रौद्योगिकी (75 डिजिटल इकाइयां स्थापित की जाएंगी), कृषि, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र (बेटरी अदला-बदली नीति) समेत अन्य क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिये आधार रखा गया है।

प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर करदाताओं के लिये चीजें सुगम बनायी गयी हैं। एक नई आयकर रिटर्न प्रणाली लायी जाएगी और राजस्व प्राधिकरणों के अपीलीय अधिकारों को सीमित कर कानूनी विवाद कम किये जाएंगे।

बजट में नई कंपनियों के लिये कर को लेकर राहत की अवधि बढ़ायी गयी है। इसके तहत 15 प्रतिशत कॉरपोरेट कर का विकल्प चुनने वाली इकाइयां अपना उत्पादन 31 मार्च, 2024 तक शुरू कर इसका लाभ ले सकती हैं।

सरकारी व्यवस्था में भरोसे को बढ़ाने के लिये अद्यतन कर रिटर्न प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत करदाता संबंधित आकलन वर्ष समाप्त होने के दो साल के भीतर निर्धारित कर के भुगतान के साथ कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया पेश करने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल संपत्तियों पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। इसमें संपत्ति की खरीद लागत को छोड़कर किसी व्यय को कटौती में शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के इरादे से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 15 प्रतिशत अधिभार की सीमा तय करने का प्रस्ताव किया।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कानून के स्थान पर नया कानून लाया जाएगा। बुनियादी ढांचा विकास को लेकर राज्य भागीदार बनेंगे।

अप्रत्यक्ष कर मामले में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिये परियोजना आयात योजना के तहत पूंजीगत सामान पर रियायती कर दर के प्रस्ताव को वापस लिया जाएगा और आयात पर 7.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com